हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 189 बेमेतरा, रविवार 01 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

क्विक न्यूज

सुको के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी

कोलकाता। उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से शुक्रवार को प्राप्त विवरणों के अनुसार अंतिम सूची से अतिरिक्त नौ लाख नाम हटाए जाने वाले हैं। ये नाम हटाने की कार्रवाई उस 58 लाख नामों से अलग है, जो प्रारूपिक मतदाता सूची से पहले ही हटा दिए गए थे, जिससे इस चरण में कुल नामों की कटौती लगभग 67 लाख हो गई है।

मंत्री देवांगन ने दी 14.42 करोड़ के अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन की सौगात

कोरबा। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 शिवाजी नगर एवं वार्ड क्रमांक 27 महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी की बहुप्रतीक्षित नई सीवरेज लाइन निर्माण 14.40 करोड़ के लागत के कार्य का नारियल तोड़कर शुभारम्भ किया। एमपी नगर स्थित उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने सम्बोधित करते हुए कहा कि दोनों ही कॉलोनी शहर के मुख्य आवासीय कॉलोनी हैं, लेकिन यहां की सीवरेज लाइन की समस्या विगत कुछ वर्षों से बदहाल थी। कॉलोनी की लंबे समय से नई सीवरेज लाइन के निर्माण की मांग थी।

एयर इंडिया की तेल अवीव जा रही उड़ान बीच रास्ते से दिल्ली वापस

नयी दिल्ली। इजरायल में उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किये जाने के बाद दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट बीच रास्ते से वापस हो गयी। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि 28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव जा रही उड़ान संख्या एआई139 बीच रास्ते से वापस दिल्ली के लिए मुड़ चुकी है। उन्होंने बताया कि इजरायल में हवाई क्षेत्र बंद किये जाने और यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान वापस आ रही है। उल्लेखनीय है कि इजरायल ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया।

ईरानी जनता को मुक्ति दिलाने और परमाणु हथियार का खतरा समाप्त करने के लिए है यह लड़ाई

वॉशिंगटन/येरुशलेम। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करते हुए कहा है कि यह लड़ाई ईरान के खतरनाक परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने और वहां की जनता को आजादी दिलाने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वॉशिंगटन में शुक्रवार रात अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई के बाद एक संबोधन में कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने और वहां क्रूर और खतरनाक लोगों की समूह की सत्ता को समाप्त कर शासन ईरान की महान और गौरवशाली जनता के हाथों में देने के लिए है। ट्रम्प ने इस लड़ाई को ईरान की आजादी का क्षण बताते हुए ईरान के सैन्य और पुलिस बलों से हथियार डालने की अपील की और उन्हें अभयदान देने का वादा किया। ट्रम्प ने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा।

ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ईरान को कभी परमाणु हथियारों से लैस नहीं होने देगा।

इजरायली हमलों से दहला ईरान

तेहरान। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों में हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने इन हमलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा, इजरायल ने अपने खिलाफ खतरों को समाप्त करने के लिए ईरान पर एहतियाती हमला किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, राजधानी में कम से कम तीन धमाकों की आवाज सुनी गयी और कुछ हिस्सों में धुआं उठता देखा गया। रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम एक हमला ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़े कार्यालयों के निकट हुआ। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अर्ध-आधिकारिक फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जुमहूरी इलाके के आसपास मिसाइलें गिरीं। सरकारी कार्यालयों वाले 'रिपब्लिक' क्षेत्र में भी विस्फोट की सूचना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत का तीसरा दौर कल ही खत्म हुआ है। इस बातचीत के समाप्त होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा था कि वह ईरान के साथ बातचीत की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ईरान पर इजरायल ने किये एहतियाती हमले : रक्षा मंत्री

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि उनके देश ने ईरान पर 'एहतियाती' हमले किये हैं। इजरायली समाचार वेबसाइट हारेत्ज़ ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि ये हमले इजरायल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई हैं। रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर संभावित ड्रोन और मिसाइल हमले कर सकता है। इस बीच, ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में तीन जगह धमाके सुने गये। ईरान ने इन हमलों के बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इजरायल ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और देश में कई जगह साइरन सुने गये।

किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित

बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिल्हा विकासखण्ड के रहंगी में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आयोजित आदान सहायता राशि वितरण समारोह एवं वृहद किसान सम्मेलन में प्रदेश के 25.28 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इनमें बिलासपुर जिले के 1 लाख 25 हजार 352 किसान शामिल हैं, जिनके खातों में 494.38 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को नई गति देते हुए 15.99 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 7 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 247.18 करोड़ रुपए की लागत के 82 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य अतिथियों का खुमरी और नांगर भेंटकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 'कृषक उन्नति योजना का वरदान, छत्तीसगढ़ का हर किसान धनवान' थीम पर आधारित वीडियो का विमोचन भी किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन किसान भाइयों के सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25 लाख 28 हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा है और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसान भाई होली का त्योहार अच्छे से मनाएं, इसलिए होली के पूर्व यह राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों की चिंता करते हुए उनके लिए प्रगतिशील योजनाएं लाई गई हैं।

इस बार किसानों को बारदाने की कोई समस्या नहीं हुई और किसानों के खातों में राशि भी समय पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण लेने की सुविधा प्रदान की है और आज लाखों किसान किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को धान की सर्वाधिक कीमत देने की व्यवस्था की गई है, जो अन्यत्र कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में भी राशि अंतरित की जा रही है। खाद में सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार सहित किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है तथा सहकारिता को लाभकारी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को 6000 रुपए सम्मान निधि की राशि प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। किसानों को खेतों में पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र से समाप्ति की ओर है और इस दिशा में हम सफल हो रहे हैं। निश्चित रूप से मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी का संकल्प पूरा होगा।

श्री बालाजी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों के एडवांस अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का सीएम साय ने किया उद्घाटन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है । मोवा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों वाली एडवांस कैंसर यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। यह यूनिट मध्य भारत के सबसे आधुनिक कैंसर उपचार केंद्रों में से एक है।

एक ही छत के नीचे सभी सुपर स्पेशियालिटी विभाग

कैंसर यूनिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मरीजों को हर प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भटकना न पड़े। यहां एक छत के नीचे गैस्ट्रो, न्यूरो, गाइनी और यूरो कैंसर विभाग, नेफ्रो, थोरेसिक (छाती) और हेड एंड नेक कैंसर विभाग है।

दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें और जांच सुविधाएं

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, यहां कैंसर के सटीक इलाज के लिए विश्वस्तरीय तकनीक का समावेश किया गया है। टू बीम रेडिएशन मशीनः सबसे एडवांस रेडिएशन थेरेपी की सुविधा। हैल्सियन लीनियर एक्सेलरेटर, ब्रेकी थेरेपीथे से एडवांस रेडिएशन थेरेपी की सुविधा।

न्यूक्लियर मेडिसिनः पीईटी-सिटी स्कैन, प्रोस्टेट कैंसर के लिए एडवांस थेरेपी और आईओडी थेरेपी।

गामा नाइफः बिना चीर-फाड़ के ब्रेन ट्यूमर के इलाज की सुविधा। वहीं 128 स्लाइस का सीटी सिमुलेटर, आईएससीई हिस्ट्रो पैथोलॉजी और फ्रोजन सेक्शन की सुविधा मौजूद है। 72 बेड का आईसीयू और बोनमैरो ट्रांसप्लांट अस्पताल में गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम साय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ के लोगो को यहाँ पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। चिकित्सीय सुविधा आयुष्मान से भी संभव हो पाएगी।

इंडिगो ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर 130 उड़ाने रद्द

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया के कई देशों में सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने वहां जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने शनिवार को अपनी 89 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही रविवार को भी उसकी 41 उड़ानें रद्द रहेंगी। एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रद्द उड़ानों की सूची का लिंक साझा किया है। इसमें मस्कट, दम्मम, दोहा, दुबई, रस-अल-खैमा, दुबई, कुवैत, अबु धाबी, शारजाह, जेद्दा, इस्तांबुल, बहरीन और मदीना शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय शहरों मैनचेस्टर (ब्रिटेन) और एम्सटर्डम (नीदरलैंड) को जाने वाली उड़ानें भी रद्द की गयी हैं। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में बताया कि वह स्थिति पर नजदीकी नजर रखे हुए है। ग्राहकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नोटिफिकेशन भेजे गये हैं। टाटा समूह की एयर इंडिया ने एक यात्रा परामर्श में बताया कि उसने पश्चिम एशिया को जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले एयर इंडिया की तेल अवीव जा रही उड़ान एआई139 को इजराइल में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण बीच रास्ते से ही दिल्ली के लिए वापस लौटना पड़ा था।

नकदी ले जा रहा सैन्य विमान क्रैश 15 की मौत

ला-पाज/नई दिल्ली। बोलीविया की राजधानी ला-पाज के पास नकदी ले जा रहा एक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि बोलिवियन वायुसेना से संबंधित हरक्यूलिस विमान देश के सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया से अन्य शहरों में नए नोट पहुंचाने के लिए उड़ान पर था। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में नोट घटनास्थल पर बिखर गए। दमकल विभाग प्रमुख पावेल टोवर ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक विमान में सवार थे या एल-आल्टो में हवाई अड्डे के पास राजमार्ग पर मौजूद वाहनों में। उन्होंने बताया कि कई लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि विमान वाहनों से टकराने के बाद एक खेत में जा गिरा। हालांकि, इस बात को लेकर विरोधाभासी खबरें हैं कि हादसा टेकऑफ के दौरान हुआ या लैंडिंग के समय। घटनास्थल पर विमान का मलबा, क्षतिग्रस्त कारें और शव बिखरे पड़े थे।

रायपुर पुलिस ने की टी-20 के दौरान करोड़ों के अवैध दांव पर कार्रवाई

रायपुर। पुलिस ने अंतरराज्यीय कार्रवाई करते हुए गोवा में संचालित एक बड़े ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया और टी-20 विश्व कप के दौरान करोड़ों रुपये के दांव लगवाने वाले इस सिंडिकेट से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत चारों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में रैंकी उर्फ सैंकी दरडा और प्रतीक वाधवानी को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए आईडी और पासवर्ड 20-20 हजार रुपये में उपलब्ध कराते थे। साथ ही सटटे की रकम की वसूली के लिए इन्होंने करीब 35 लाख रुपये में एक विशेष 'पैनल' खरीदा था, जिसके जरिए हारने वाले सटोरियों से वसूली की जाती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के तार चर्चित ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म 'महादेव सटटा' से जुड़े प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी सीधे संपर्क में रहकर रकम की वसूली करते थे और बदले में मोटा कमीशन प्राप्त करते थे। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से आरोपियों ने गोवा में एक आलीशान विला किराए पर लिया था, जहां से पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किये

राजस्थान विकास के नये पथ पर अग्रसरः प्रधानमंत्री मोदी

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संतोष है कि राजस्थान विकास के नये पथ पर अग्रसर हैं और विकास के जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार यहां लोगों की सेवा में आयी थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है।

मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले भी प्रदेश की भाजपा की डबल इंजन सरकार के दो साल पूरे हुए हैं और उन्हें संतोष है कि राजस्थान विकास नये पथ पर अग्रसर हैं। आज का दिन भी विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है और थोडी देर पहले यहां राजस्थान विकास से जुडी करीब 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में नयी शक्ति जुड रही है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ायेंगे, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है और दो साल पहले तक राजस्थान से भर्ती में भष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें आती रहती थी।

अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपें गये हैं। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा बदलाव आया हैं और इस बदलाव के लिए नयी नौकरियों के लिए विकास के सभी कामों के लिए प्रदेश के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि उन्हें वीरांगनाओं की धरती राजस्थान से देश भर की बेटियों के लिए अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है और यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम हैं। सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है, तो घर बिखरता जाता है, मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता हैं। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलायी हैं। उन्होंने कहा, आपने वर्ष 2014 से पहले का दौर देखा है कि शौचालय के अभाव में महिलाओं को पीड़ा एवं अपमान झेलना पडता था। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। पहले सत्ता में जो रहे, उनके लिए ये छोटी बातें होती थी, लेकिन हमारे लिए यह बहन-बेटियों को बीमार करने वाले उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए इसका मिशन मोड़ पर समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलायी गयी और महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना बनायी गयी, यह सब इसलिए संभव हुआ कि हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हैं और डबल इंजन सरकार राजस्थान में विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है।

भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर जतायी चिंता, बातचीत से मुद्दों के समाधान पर दिया जोर

नयी दिल्ली। भारत ने ईरान पर अमेरिका तथा इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से मुद्दों का समाधान करने पर बल दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि भारत ईरान और खाड़ी क्षेत्र में ताजा घटनाक्रम पर अत्यधिक चिंतित है।

मंत्रालय ने कहा है कि भारत का सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह है। वक्तव्य में कहा गया है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से तनाव कम कर मुद्दों का समधान किया जाना चाहिए। प्रभावित देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में मंत्रालय ने कहा, इस क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और परामर्श जारी कर उन्हें सतर्क रहने तथा मिशन कार्यालयों के संपर्क में रहने के साथ -साथ स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम एशिया स्थित सात देशों ईरान, इजराइल ,कतर, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत स्थित भारतीय दूतावासों ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है और आपात स्थिति में दूतावासों से आपात टेलीफोन नम्बरों तथा इमेल पर संपर्क करने को कहा था। इनमें से कई दूतावासों ने पिछले कुछ दिनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इन देशों से चले जाने की सलाह दी थी।

46 लाख से अधिक नकदी रकम और भारी मात्रा में हथियार बरामद

मैनपुर। नक्सल विरोधी अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मैनपुर अंतर्गत ग्राम कड़ेदोरा के सांपसाटी नामक जंगल/पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा डंप कर रखी गई नकदी, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एस-30 टीम एवं थाना मैनपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने 28 फरवरी को जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया सघन तलाशी के दौरान अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मौके से कुल 46,31,500/- (छियालीस लाख इकतीस हजार पांच सौ रुपये) नगद, एक भरमार बंदूक, एक एलएमजी बट (स्पेयर), 33 नग भरमार कारतूस, 01 सटका रायफल, 32 डीजल इंजन सेल, 01 लैपटॉप, 02 मोबाइल, 10 इंसास राउंड, 11 एसएलआर राउंड, 45 एके-47 राउंड, 41 नग .303 राउंड, 23 विभिन्न शॉटगन राउंड, 26 नग 12 बोर राउंड, 13 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 10 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य नक्सली उपयोग की सामग्री जब्त की है पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

इस सफलता से नक्सली संगठन को आर्थिक एवं सामरिक रूप से बड़ा झटका लगा है जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कांकेर के 92 हजार से अधिक किसानों के खातों में बरसे 372 करोड़, 'कृषक उन्नति योजना' से खिले अन्नदाताओं के चेहरे

कांकेर /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज प्रदेश के अन्नदाताओं के सम्मान में एक बड़ा कदम उठाया है। 'कृषक उन्नति योजना' के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर के 24 लाख 28 हजार किसानों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कृषि आदान सहायता राशि एकमुश्त अंतरित की। इसी कड़ी में कांकेर जिले के 92 हजार 493 किसानों के खातों में 372 करोड़ 67 लाख 20 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। बिलासपुर से हुआ राज्य स्तरीय आयोजन मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में रिमोट का बटन दबाकर यह राशि अंतरित की। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र, सिंगारभाट कांकेर के परिसर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विधायक आशाराम नेताम ने कहा- ÷किसानों की मेहनत का मिला सम्मान÷-कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जोड़ी किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, ÷प्रदेश के मुखिया ने प्रत्येक अन्नदाता की मेहनत को वास्तविक सम्मान और हक 'कृषक उन्नति योजना' के जरिए दिया है।÷ उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसायों को भी अपनाएं ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से लाभान्वित किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए, ग्राम कोकपुर के प्रेमलाल जैन, बेवरती के पीलाराम नेताम और पोटगांव के मानेश कुल्हरिया सहित 10 किसानों को वितरित किया गया।आदिवासी उप योजना के तहत दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मोहपुर और बाड़ाटोला के 15 किसानों को मिनी किट दी गई। इस गरिमामयी अवसर पर राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, जनपद पंचायत अध्यक्ष पूर्णिमा कावड़े, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी और एसडीएम अरुण वर्मा, कृषि विभाग अधिकारी जितेन्द्र कोमरा एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारीगण और काफी संख्या में कृषक मौजुद थे।

कुसमी में किसान सम्मेलन सहायता राशि वितरण, विधायक उद्देश्वरी पैकरा का मनाया गया जन्मदिन

सभा कक्ष में केक काटकर और मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच बांटी गई खुशियां

कुसमी/मूक पत्रिका

जनपद सभा कक्ष में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह एवं बृहद किसान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए। इस दौरान किसानों को शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को आदान सहायता राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, उर्वरक उपयोग, फसल विविधीकरण एवं उत्पादन बढ़ाने के उपायों के संबंध में भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि शासन की मंशा है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। कार्यक्रम के समापन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा का जन्मदिन भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभा कक्ष में केक काटकर तथा मिठाई खिलाकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, किसानों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर ने जीता संयुक्त राष्ट्र की मेंटर का दिल, प्रवास के बाद भावुक होकर विदा हुई सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन

जगदलपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के बस्तर की गौरवशाली संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इन दिनों वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र की मेंटर और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन ने अपने छह दिवसीय प्रवास के दौरान बस्तर की अद्वितीय परंपराओं का अनुभव किया। अपने इस सफल भ्रमण के समापन पर शनिवार को उन्होंने बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा से औपचारिक मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन भी उपस्थित रहे, जहां बस्तर के पर्यटन और विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर आकाश छिकारा और सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन से ?मुलाकात के दौरान सुश्री किर्सी ने विशेष रूप से धुड़मारास भ्रमण के अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि यहां की स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने बस्तर के स्थानीय लोगों के अतिथि सत्कार और सदियों पुरानी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सुश्री किर्सी का मानना है कि बस्तर की जड़ें अपनी परंपराओं में इतनी गहरी हैं कि यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय गंतव्य बन सकता है। ?विगत छह दिनों से बस्तर के विभिन्न अंचलों का भ्रमण करने के बाद शनिवार को सुश्री किर्सी ने यहां से विदाई ली। कलेक्टर आकाश छिकारा ने उनके अनुभवों को बस्तर के पर्यटन संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ का बस्तर को समझने-बूझने का यह भ्रमण न केवल स्थानीय पर्यटन को नई पहचान दिलाने में सहायक होगा, बल्कि बस्तर की लोक कला और परंपराओं को वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन देने पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा छत्तीसगढ़ स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के हड़ताल को समर्थन देने के लिए हड़ताल स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन व्यक्त किया इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को झूठे वादे और कोरी कल्पनाएं दिखाकर सत्ता हासिल कर ली है लेकिन आज सभी वर्ग चाहे वह किसान हो या कर्मचारी हो इस सरकार से परेशान और निराश हो चुके हैं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शासकीयकरण की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए इन्हें भी शासकीय कर्मचारियों के समान सभी सुविधाओं को प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें इनका पेंशन चिकित्सा पूर्ति सहित तमाम तरह की सुविधा जो शासकीय कर्मचारियों को मिलती है उन्हें दिए जाना चाहिए साथ ही साथ संघ द्वारा हड़ताल में जिन मुद्दों पर सरकार से माग की जा रही है उन सभी मांगों का भी समर्थन करता हूं ललित विश्वकर्मा श्रीमति रश्मि मिश्रा श्रीमति शकुन्तला साहू श्रीमति शशि प्रभा गायकवाड सुमन गोस्वामी मनोज शर्मा रवि रजक चंद्र प्रकाश शीतलानी विद्या जैन सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

पीएम-राहत योजनाः दुर्घटनाग्रस्त पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक मिलेगा फ्री में 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री राहत योजना का शुभारंभ पिछले पखवाड़ा में किया गया। पूर्व में यह योजना CTRAV के नाम से जानी जाती थी। योजना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 50त्न मौतों को समय पर अस्पताल में भर्ती कराकर रोका जा सकता है। पीएम-राहत योजना का उद्देश्य 'गोल्डन आवर' के दौरान त्वरित और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल हाइवे के द्बष्ठक्र प्लेटफॉर्म तथा National Health Authority के ञ्जरूस्- 2.0 के एकीकृत डिजिटल तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिससे दुर्घटना रिपोर्टिंग से लेकर क्लेम निपटान तक की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। अस्पतालों को भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के माध्यम से किया जाएगा तथा स्वीकृत दावों का भुगतान 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसी भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को आर्थिक अभाव के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न होना पड़े।

होली पर विद्युत सुरक्षा को लेकर अपीलखंभों, लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के निकट न करें होलिका दहन मुख्य अभियंता की चेतावनी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने होली पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों एवं मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। कंपनी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक विद्युत दुर्घटना को रोकने के लिए समुचित अमले के साथ शिकायत केंद्रों में पूरी तैयारी रखी गई है। दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं की जागरूकता और शालीनतापूर्वक रंगोत्सव मनाना विद्युत कंपनी सहित आमजन के लिए हितकारी होगा। उन्होंने विशेष रूप से अपील की है कि विद्युत उपकेंद्रों, खंभों, लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों के निकट होलिका दहन न करें और रंगों की बौछार भी इन पर न डालें, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट या अन्य गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मुख्य अभियंता ने बताया कि होली के अवकाश के बावजूद बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कंपनी का केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 चौबीसों घंटे सामान्य दिनों की भांति कार्यरत रहेगा। उपभोक्ता इस नंबर पर हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ÷बिजली मितान बॉट÷ के व्हाट्सऐप नंबर 9425551912 पर भी बिजली आपूर्ति बाधित होने, ट्रांसफॉर्मर खराबी अथवा अन्य विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ता ÷मोर बिजली ऐप÷ के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे विद्युत लाइनों या ट्रांसफार्मरों पर कोई वस्तु न फेंकें, रंगों की बौछार न करें तथा किसी भी प्रकार की विद्युत गड़बड़ी या दुर्घटना की सूचना तत्काल निकटस्थ विद्युत कार्यालय को दें। होलिकोत्सव के दौरान बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री साय ने धान बिक्री किये 84058 किसानों को दिया 3237.96 लाख रूपये

कृषक उन्नत योजना के तहत मिला समर्थन मूल्य का अंतर राशि

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला मुख्यालय में कृषक उन्नत योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह का आयोजन शुक्ला भवन सारंगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और सरकार की विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 442948.84 मे.टन धान विक्रय के भुगतान राशि 104934.58 लाख रूपये जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 84058 किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से अंतर राशि 3237.96 लाख रुपये का हस्तांतरण बटन दबाकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, सदस्य लता लक्ष्मे, शिवकुमारी साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष सारंगढ़ ममता ठाकुर, पूर्व विधायक कामदा जोल्हे, सत्ता धारी दल के जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव, खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे, पत्रकारगण आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे द्वारा किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में ग्राम सालर के किसान चोकलाल को बोनस राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र पाकर किसान ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। 14 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरित किए गए। हितग्राही महिलाओं ने योजना का लाभ मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

नौघटा के नया बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर सरपंच और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के प्रयास से जल्द पूरी हुई मांग..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

तहसील सरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नौघटा के नया बस्ती में लंबे समय से ट्रांसफार्मर की मांग चल रही थी। बार-बार समस्या उठने के बाद आखिरकार गांव को बड़ी राहत मिल गई है। नया बस्ती में नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस काम को जल्द पूरा कराने में सरपंच संगीता विरेन्द्र पटेल की अहम भूमिका रही। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने समस्या को गंभीरता से लिया और लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा। वहीं भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जवाहर नायक का भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रयासों से प्रक्रिया में तेजी आई और ट्रांसफार्मर समय से पहले स्थापित हो सका।

बिजली समस्या से मिली राहत

नया बस्ती में ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बार-बार बिजली संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कम वोल्टेज और ओवरलोड की समस्या आम थी। अब नया ट्रांसफार्मर लगने से बिजली आपूर्ति सुचारू होने की उम्मीद है।गांव के लोगों का कहना है कि पंचायत स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान होना बड़ी बात है। उनका मानना है कि छोटा हो या बड़ा, हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसफार्मर लगने के बाद अब नया बस्ती के घरों में नियमित बिजली मिलने लगेगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू काम और छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ मिलेगा। गांव में इसे विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निभाया वादा होली से पहले खातों में पहुंची राशि, राज्यभर में 10,324 करोड़ रुपये का हुआ अंतरण

कृषक उन्नति योजना: जिले के 1 लाख 54 हजार से अधिक किसानों को 631 करोड़ 30 लाख रुपये की आदान सहायता राशि अंतरित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के उपरांत आज 'कृषक उन्नति योजना' के तहत अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया गया। होली पर्व से पूर्व राशि मिलने से जिले के किसानों में उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रहंगी खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना अंतर्गत राशि का अंतरण किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों में किया गया, जिनमें बेमेतरा जिला भी वर्चुअली जुड़ा रहा।

जिले में 631.30 करोड़ रुपये का हुआ अंतरण-जिले के 1 लाख 54 हजार 995 अन्नदाता किसानों को कुल 631 करोड़ 30 लाख रुपये की आदान सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। वर्ष 2025-26 में जिले की 102 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 129 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 1,54,995 किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से लगभग 86 लाख 44 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई। समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान पूर्व में ही किसानों को किया जा चुका है। बीते शनिवार को कृषि उन्नति योजना के तहत सामान्य धान पर 731 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान पर 711 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता राशि का अंतरण किया गया। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा धान का कुल भुगतान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सुनिश्चित किया गया। प्रदेश स्तर पर 25 लाख 28 हजार से अधिक पंजीकृत धान एवं धान बीज उत्पादक किसानों को 10,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।

टाउन हॉल, बेमेतरा में हुआ वृहद किसान सम्मेलन-जिला मुख्यालय बेमेतरा में कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा जय दिवाकर, कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती हेमलता पदमाकर सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

जिले के अन्य विकासखंडों में कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित हुए-बेमेतरा ङ्क टाउन हॉलसाजा ङ्क ग्राम सुवरतालनवागढ़ ङ्क मंगल भवनबेरला ङ्क सामुदायिक भवनसभी स्थलों पर राशि अंतरण का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

विधायक दीपेश साहू का संबोधनः ÷यह किसानों के परिश्रम का सम्मान÷-विधायक दीपेश साहू ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है और यहां का किसान मेहनती, जागरूक एवं प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से किया गया वादा निभाते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल एवं 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की है।उन्होंने कहा कि 631 करोड़ 30 लाख रुपये की यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसानों के परिश्रम का सम्मान है। इससे आगामी फसल के लिए बीज, खाद, कीटनाशक एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था में सहायता मिलेगी। विधायक साहू ने बताया कि किसानों की मांग पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अमोरा बैराज निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही 6 नए विद्युत सब-स्टेशनों की स्वीकृति से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी।

जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार-नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों के हित में संवेदनशील निर्णय ले रही है। समय पर भुगतान से किसानों का विश्वास और मजबूत हुआ है। जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमा जय दिवाकर ने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में भी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी।

योजना का उद्देश्यः कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना-छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। वर्षा आधारित खेती, लागत में वृद्धि एवं मौसमीय अनिश्चितता के कारण किसानों की आय प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि उन्नति योजना प्रारंभ की है, ताकि किसान उन्नत बीज, उर्वरक, यांत्रिकीकरण एवं आधुनिक तकनीक में निवेश कर सकें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके।

प्रेस क्लब गठन-संजय सिंह अध्यक्ष जगदीश माहेश्वरी उपाध्यक्ष,प्रेस क्लब का सर्वसम्मति से गठन, पत्रकार हितों की मजबूती का संकल्प

सुकमा /मूक पत्रिका

जिले के पत्रकारों की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सुकमा जिला प्रेस क्लब का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं, जिससे संगठन को सशक्त और प्रभावी नेतृत्व मिल सके। संघ के अध्यक्ष पद पर संजय (रिंटू) सिंह भदौरिया को मनोनीत किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में अमन सिंह भदौरिया एवं जगदीश महेश्वरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव पद की जिम्मेदारी पवन शाहा को, सह सचिव के रूप में रफीक खान को तथा कोषाध्यक्ष के रूप में लीलाधर राठी को नियुक्त किया गया है। संगठन को अनुभवी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु वरिष्ठ पत्रकार पीसा राजेंद्र, जोगराज जैन, आशीष दुबे एवं राजा राठौर को संरक्षक की भूमिका में रखा गया है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संघ को नई दिशा और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त 13 पत्रकारों को कार्यसमिति सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो संगठन की गतिविधियों, कार्यक्रमों और पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नवगठित संघ ने स्पष्ट किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान,अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष पत्रकारिता के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जिले में पत्रकारों के बीच समन्वय,संवाद और सहयोग की भावना को और मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। जिले के पत्रकारों ने इस गठन को ऐतिहासिक बताते हुए उम्मीद जताई है कि सुकमा जिला पत्रकार संघ आने वाले समय में पत्रकार हितों की आवाज बुलंद करेगा और संगठनात्मक एकता का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। कार्य समिति सदस्य - डमरू राम, जयपाल सिंह,नवीन डांधडे,सुजीत वैदिक,राहुल राजपूत,समीर कीर्तन,ज्ञानेंद्र सिंह,अंकित चौहान,माड़वी पवन,राजकुमार श्रीवाने, गौरव सिंह राठौर,आदर्श शुक्ला,वरुण नायडू,मोहम्मद रफीक

अघोषित बिजली कटौती के खिलाफकांग्रेस का प्रदर्शन, 132 केवी सब स्टेशन निर्माण जल्द शुरू करने की मांग, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन..

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

सरिया क्षेत्र में जारी अघोषित बिजली कटौती और प्रस्तावित 132 केवी विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराज कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।नगर के महात्मा गांधी चौक से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार कोमल साहू को मांगपत्र सौंपा। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित कटौती से आम नागरिक, किसान और छात्र बुरी तरह प्रभावित हैं।

डेढ़ साल पहले मिली थी स्वीकृति-कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरिया में प्रस्तावित 132 केवी सब स्टेशन को लगभग डेढ़ वर्ष पहले स्वीकृति मिल चुकी है। यह परियोजना क्षेत्र के विकास और किसानों की बढ़ती विद्युत जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

आंदोलन की चेतावनी-ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अग्रसेन साहू, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी शरद यादव और एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष निखिल डनसेना के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। शरद यादव ने कहा कि सरिया क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। यहां के किसान मेहनत और आधुनिक तरीकों से खेती कर रहे हैं, लेकिन बार-बार बिजली कटौती से सिंचाई और अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

जिला शिक्षा विभाग ने शपथ लेकर मनाया होली पर्व

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कार्यालय जिला शिक्षा विभाग जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने रंगों का पर्व होली पर्व को सौहार्द, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए मनाया।इस अवसर पर जिला कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एकत्रित होकर रंगों के इस पावन पर्व पर आपसी भाईचारा, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का शपथ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीईओ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जे. आर.डहरिया के स्वागत उद्बोधन से हुई।डीईओ ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है बल्कि आपसी मतभेदों को मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश देने का अवसर है। सभी को स्वच्छ,सुरक्षित और शांति पूर्ण होली मनाने अपील किया।

उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए,जल संरक्षण का ध्यान रखेंगे तथा समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने हेतु सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दिया तथा सुरक्षित व स्वच्छ होली मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला कार्यालय सहायक सोमा सिंह ठाकुर, बीईओ सारंगढ़ रेशम कोशले, बीआरसीसी सत्येंद्र बसंत, जिला क्रीड़ा अधिकारी फक्कीरा यादव, दीपक तिवारी, जिला अध्यक्ष भागवत प्रसाद साहू, तरुण कुमार रात्रे, पंकज साहू, रविन्द्र पटेल, डाबर सिंह साहू,मनोज मेहर, वासुदेव महापात्रे, किरण लहरे, दीप्ति वर्मा, पूर्णिमा महिलाने, खीरमती पटेल , आशीष पटेल, राधेश्याम बसंत, तेजराम जोल्हे , संजू मीरी, गजेंद्र यादव, शिवम् यादव, चंद्रा मैडम, साहू मैडम आदि उपस्थित रहें।

गांडा समाज के हक की गूंजः 5 एकड़ भूमि और 2 करोड़ की मांग को लेकर तेज हुई पहल

विधायक चातुरी नंद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से की मुलाकात

सारंगढ़ /मूक पत्रिका

मूल छत्तीसगढ़िया गांडा समाज और सराईपाली विधायक चातूरी नन्द के अगुवाई मे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से चातुरी नंद ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा, बल्कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी विशेष मुलाकात कर समाज के लिए 5 एकड़ भूमि और 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की जोरदार मांग रखी।विधायक ने स्पष्ट कहा कि मूल छत्तीसगढ़िया गांडा समाज वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है, लेकिन आज भी समाज के पास स्वयं का स्थायी भवन या पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में नया रायपुर क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि सामाजिक भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाए तथा भवन निर्माण और आवश्यक अधोसंरचना के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाए।

÷समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए÷-वित्त मंत्री ओपी चौधरी से हुई चर्चा के दौरान विधायक ने बजट में समाज के लिए अलग से प्रावधान नहीं होने पर चिंता जताई और आगामी बजट या विशेष स्वीकृति के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अन्य समाजों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं तो गांडा जाति की अनदेखी क्यों? प्रदेश में गांडा जाति की संख्या बहुत बड़ी तादाद में निवासरत है और अनुसूचित जाति का हिस्सा हैं।

उम्मीदों की नई किरण-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद समाज के लोगों में उम्मीद बढ़ी है। क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और समाज अब सरकार के सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

विधायक चातुरी नंद ने विश्वास जताया कि सरकार समाज की भावनाओं को समझते हुए शीघ्र उचित निर्णय लेगी और मूल छत्तीसगढ़िया गांडा समाज को उसका हक दिलाएगी। इस अवसर पर चातूरीनन्द विधायक सराईपाली, देवशरण नाग ,गोपाल बाघे,सुभाष चौहान, संकीर्तन नन्द,देवराज दीपक ,किशोर नन्द,लक्ष्मी नाग,गोदावरी करैत,सुन्दरदास कुलदीप,मुकेश करैत, मन्थिर चौहान, आनंद चौहान, दिगम्बर चौहान, मुकेश देवदास,परसराम देवदास,तोमन सिंग ,मदन भारती, रामा खेमराज बघेल,महेंद्र जगत,के अलावा दर्जनों समाजिक कार्यकर्ताओं उपस्थित थे।

मोदी की गारंटी के तहत वेतन विसंगति दूर करने जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने सीएम व वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की ओर से आज विधानसभा भवन में सहायक शिक्षकों की वर्षों पुरानी वेतन विसंगति का मुद्दा को निवेदन कर बताया। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भेंट कर विस्तृत चर्चा की तथा मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

वन टाइम रिलैक्सेशन की प्रमुख मांग-जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मामला लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आर्थिक असमानता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांग रखी कि जिन सहायक शिक्षकों को अब तक क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान कर क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही असमानता समाप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि ÷मोदी की गारंटी÷ के तहत प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में सकारात्मक कदम उठाने का वादा किया है। ऐसे में सहायक शिक्षकों को न्याय मिलना आवश्यक है।

शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है जिससे-फेडरेशन ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वेतन विसंगति के कारण कई शिक्षक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। समान कार्य करने के बावजूद वेतन में अंतर होने से मनोबल प्रभावित होता है। यदि सरकार समय रहते निर्णय लेती है, तो न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी और अधिक सशक्त होगी।

सरकार ने दिया आश्वासन-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बातों को गंभीरता से सुना और विषय पर सकारात्मक परीक्षण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा।

फेडरेशन को फैसले की उम्मीद-मुलाकात के बाद फेडरेशन पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार जल्द ही सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा जाएगा, परंतु फिलहाल सरकार के सकारात्मक रुख से शिक्षकों में आशा की किरण जगी है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षक अब सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी न्यायसंगत वेतनमान का लाभ मिल सके और वे पूर्ण मनोयोग से शिक्षा कार्य में जुट सके और मोदी की गारंटी भी पूरा हो और शिक्षा जगत मे रौनक लौटे !

होली के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग रहेंगे अलर्ट मोड़ में, घूमेगी पेट्रोलिंग गाड़ियां, हॉस्पिटल में रहेंगे डॉक्टर और उनकी टीम

सड़क रोककर जबरन चंदा वसूली जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित

नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

आगामी होली और रमजान पर्व को शांतिपूर्ण एवं सदभाव वातावरण में मनाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के सदस्य, पत्रकारगण उपस्थित रहे।बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि होली के दौरान कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में वाहन न चलाए तथा शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने त्योहार के दौरान अभद्र व्यवहार न करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की।होलिका दहन केवल निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। डामरीकरण (पक्की) सड़कों पर होलिका दहन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि सड़कों को नुकसान न पहुंचे। इस वर्ष होलिका दहन 2 तारीख की रात्रि में किया जाएगा। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति के डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफउपलब्ध रहे, ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल कर सहायता लेने की अपील की गई है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि शांति समिति की बैठक का उद्देश्य समाज और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि जिले में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। उन्होंने जिलेवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ पर्व मनाएं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सड़क रोककर जबरन चंदा वसूली जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित है, ऐसा न हों। आमजन एवं महिलाओं को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही किसी को जबरदस्ती गुलाल न लगाने और शासकीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली और रमजान दोनों महत्वपूर्ण पर्व हैं, जिन्हें आपसी सद्भाव और शांति के साथ मनाना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

कृषक उन्नति योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर के अन्नदाता के खातों में भेजी अंतर की राशि

सुकमा जिले के 14549 किसानों के खातों में 63 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि अंतरित

सुकमा /मूक पत्रिका

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत आज प्रदेश के 24 लाख 28 हजार किसानों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि एकमुश्त अंतरित की गई। इसके तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान बेचने वाले सुकमा जिले के 14 हजार 549 किसानों के खातों में आज 63 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर के बिल्हा विकासखण्ड के ग्राम रहंगी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दोपहर को रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश भर के किसानों के खातों में योजनांतर्गत एक साथ राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के लाभार्थी किसानों से वर्चुअल रूप से वार्तालाप भी किया। सुकमा जिले में कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में विकासखंड स्तर पर समारोह का सीधा प्रसारण शबरी ऑडिटोरियम सुकमा, जनपद पंचायत छिंदगढ़ और सामुदायिक भवन कोंटा परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सुकमा में नगरपालिका अध्यक्ष श्री हुंगाराम मरकाम, छिंदगढ़ में जनपद उपाध्यक्ष सुकमा श्रीमती रीना पेद्दी और कोंटा में जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता कोवासी शामिल हुई। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने किसानो को संबोधित करते हुए आदान राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। कृषकों की आय दुगनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के किसानपुत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किसान हित में लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया ने प्रत्येक अन्नदाता की मेहनत को उनका वास्तविक सम्मान और हक कृषक उन्नति योजना के जरिए दिया है। किसानों को धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, उतेरा फसलों के अलावा पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन जैसे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और वे आर्थिक रूप से समृद्ध व आत्मनिर्भर बन सकें। उल्लेखनीय है कि खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में धान बेचने वाले सुकमा जिले के 14 हजार 549 किसानों के बैंक खातों में कुल 63 करोड़ 40 लाख 5 हजार रूपए की राशि आज मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा अंतरित की गई। इन किसानों के द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में 8 लाख 67 हजार 309 क्विंटल धान बेचा गया था, जिनकी अंतर राशि 21 बैंक शाखाओं में किसानों के बैंक खातों में एकमुश्त जमा हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्नू, श्री हुंगाराम मरकाम, श्रीमती संजना नेगी, श्रीमती माड़े बारसे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री डमरू राम नाग, जनप्रतिनिधि श्री दिलीप पेद्दी, श्री संजय सोड़ी, श्री विक्रांत सिंहदेव, श्री प्रवीण बारसे, एसडीएम छिंदगढ़ श्री पीवी खेस, एसडीएम सुकमा श्री सूरज कश्यप, जनपद सीईओ कोंटा श्री सुमीत ध्रुव, तहसीलदार श्री गिरीश निंबालकर, उपसंचालक कृषि श्री पीआर बघेल के अलावा स्थानीय जनपद सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे।

संपादकीय

बढ़ते हादसे और गिरता भरोसा

झारखंड में चतरा जिले के कर्माटाड जंगल में सोमवार शाम एक चार्टर्ड एअर एंबुलेंस के हादसे का शिकार होने और उसमें सभी सात लोगों की मौत ने एक बार फिर इस सवाल को गहरा किया है कि क्या दिनोंदिन विमान सेवाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। गौरतलब है कि एक मरीज और उनके परिजनों को दिल्ली ले जा रही एअर एंबुलेंस मौसम खराब होने की वजह से मार्ग बदलने की कोशिश कर रही थी। मगर थोड़ी देर बाद यह विमान रडार से गायब हो गया और कुछ समय बाद उसका मलबा घने जंगल में मिला।यह हादसा पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही वैसी घटनाओं की एक कड़ी है, जिनसे विमान यात्रा के पूरी तरह सुरक्षित होने की धारणा कमजोर होती है। झारखंड में हुए हादसे के अगले ही दिन मंगलवार को दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण वापस उतारना पड़ा।इसके अलावा, सरकारी कंपनी पवन हंस के एक हेलिकाप्टर को अंडमान क्षेत्र में उड़ान के दौरान तकनीकी कारणों से समुद्र में आपात अवस्था में उतारना पड़ा। गनीमत रही कि इसमें सवार सभी सात लोगों को बचा लिया गया। दो दिन के भीतर होने वाली ये घटनाएं बताती हैं कि हाल के वर्षों में यात्रा के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही विमान सेवा अब कई स्तर पर जोखिम से गुजर रही है। जबकि विमान यात्रा को कहीं आने-जाने का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता रहा है।आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ समय से लगातार विमानों के हादसे का शिकार होने से लेकर उड़ान के बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस उतारने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है? विमान सेवाओं के मामले में एक आम स्थिति यह है कि समय-समय पर तकनीकी स्तर पर हर पहलू से उच्च स्तरीय जांच होती है और हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही उसे उड़ान के लिए तैयार माना जाता है।हर उड़ान के पहले सुरक्षा जांच की एक सघन प्रक्रिया पूरी की जाती है, ताकि बीच रास्ते में कोई अड़चन न आए। मगर हाल के समय में कई विमानों की उड़ान के बाद रास्ते में तकनीकी खराबी का पता चलने पर वापस उतारने की घटनाएं यह बताती हैं कि या तो तकनीकी स्तर पर उसमें कोई खराबी थी या फिर सुरक्षा जांच में किसी स्तर पर कमी की गई।इसी महीने के शुरू में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि भारतीय विमान सेवा के जिन विमानों की तकनीकी जांच हुई, उनमें से लगभग आधे में बार-बार खराबी पाई गई।इस क्रम में पिछले वर्ष जनवरी से छह बड़ी एअरलाइंस के 754 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 377 में बार-बार खामी आने की बात सामने आई। गड़बड़ियां पाई गईं, वे कितनी संवेदनशील थीं और उनसे पैदा होने वाले जोखिम का स्तर क्या था। नजरअंदाज करके या उसे सुरक्षा से संबंधित नहीं मान कर उड़ान की इजाजत दी जाती है।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और डाटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए तो भारत एआई अनुसंधान और नवाचार में विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली इन दिनों केवल भारत की राजनीतिक राजधानी भर नहीं, बल्कि उभरती तकनीकी चेतना का वैश्विक केंद्र बनी हुई है। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब प्रयोगशालाओं या कॉरपोरेट दफ्तरों तक सीमित तकनीक नहीं रही, बल्कि वह विकास की नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर है। दुनिया के विभिन्न देशों, तकनीकी कंपनियों, शोध संस्थानों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को वैश्विक विमर्श का मंच बना दिया है।

भारत का एआई नेतृत्व तकनीक एवं मानवीय मूल्यों का संगम बने

(ललित गर्ग)

यह आयोजन इस तथ्य का उद्घोष है कि भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि एआई युग का नेतृत्वकर्ता बनने की तैयारी में है। आज विश्व जिस तकनीकी संक्रमण से गुजर रहा है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णायक भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास-हर क्षेत्र में एआई समाधान की नई संभावनाएँ खोल रहा है। ऐसे समय में भारत का दृष्टिकोण केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं, बल्कि वह इसे मानव-केंद्रित विकास के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि तकनीक का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा होना चाहिए, न कि केवल लाभ और वर्चस्व की दौड़।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और डाटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए तो भारत एआई अनुसंधान और नवाचार में विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो वास्तविक शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, न कि केवल झूठे दावों और विज्ञापन के बल पर प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास करें। शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता ही उस आधारशिला को मजबूत करेगी जिस पर भारत का एआई भविष्य खड़ा होगा। यह सवाल उठाया जा रहा है कि भारत आज व्यवहार में एआई व रोबोटिक्स के अनुसंधान में कहां खड़ा है? आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नीति-नियंताओं ने यह क्यों नहीं सोचा कि चीन निर्मित एक रोबोट को अपनी उपलब्धि बताने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी? अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि उसने रोबोट के निर्माण का दावा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उन सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना जांच-पड़ताल के विश्वविद्यालय को एआई समिट में स्टॉल लगाने की अनुमति क्यों दी। निश्चित रूप से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक व रोबोटिक उत्पादन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। युवा शक्ति के देश भारत ने एआई के क्षेत्र में अमेरिका व चीन के बाद अपना तीसरा स्थान बनाया है। जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ने भी की है। लेकिन एक विरोधाभासी हकीकत यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है, जहां श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की भूमिका क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। रोगों की प्रारंभिक पहचान, सटीक निदान, दवाओं के शोध और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार में एआई नई संभावनाएँ लेकर आया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण है, वहाँ एआई आधारित समाधान

दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सेवाएँ पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान, मृदा विश्लेषण, फसल प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन में एआई किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का माध्यम बन सकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी आज मानवता के सामने विकराल रूप में उपस्थित है। चरम मौसम की घटनाएँ, जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन विकास की गति को प्रभावित कर रहे हैं। एआई आधारित मॉडलिंग और डेटा विश्लेषण से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और टिकाऊ नीतियों का निर्माण संभव है। यदि भारत इन क्षेत्रों में एआई का प्रभावी उपयोग करता है तो वह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।

शासन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी एआई पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार पर अंकुश, नीति निर्माण में डेटा-आधारित निर्णय और वित्तीय समावेशन के विस्तार में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होंगी, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। आर्थिक दृष्टि से एआई नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और विनिर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा भर सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। किन्तु इस उजाले के साथ कुछ गहरी छायाएँ भी हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव से रोजगार संरचना में परिवर्तन स्वाभाविक है। अनेक पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं और नई कौशल-आधारित नौकरियों की माँग बढ़ेगी। यदि कौशल विकास और पुनर्प्रशिक्षण पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो असमानता और बेरोजगारी की समस्या गहरा सकती है। इसी प्रकार डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, डीपफेक और निगरानी जैसे प्रश्न लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन सकते हैं। तकनीक का दुरुपयोग सामाजिक विभाजन और सूचना के दुष्प्रचार को बढ़ा सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि एआई के विकास के साथ नैतिक ढाँचे और नियामक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। भारत को ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जिसमें नवाचार की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलन बना रहे। मानवता केंद्र में का सिद्धांत केवल नारा न बने, बल्कि नीति और व्यवहार में परिलक्षित हो। एआई का उपयोग यदि समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए किया जाए तो यह तकनीक समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसरों का द्वार खोल सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन और अमेरिका एआई के क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत के सामने चुनौती है कि वह इस दौड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशाल बाजार उसे एक अलग सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि वह अनुसंधान में निवेश, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे तो वह एआई के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सस्ती, सुलभ और मानव-केंद्रित तकनीक उपलब्ध कराकर भारत एक नैतिक नेतृत्व स्थापित कर सकता है।

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भविष्य की संरचना का प्रारूप है। यहाँ से निकले संकल्प यदि नीति और क्रियान्वयन में रूपांतरित होते हैं तो भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकेगा। यह अवसर है कि हम एआई को केवल आर्थिक लाभ का साधन न मानें, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन और मानव कल्याण के माध्यम के रूप में देखें। आज जब दुनिया में मानवीय मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय है, तब भारत के पास अवसर है कि वह तकनीक और नैतिकता के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करे। एआई का विकास यदि करुणा, समावेशन और सतत विकास के आदर्शों के साथ हो तो यह मानवता के लिए वरदान सिद्ध होगा। भारत को अपने युवाओं, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई की यात्रा मानवता के उत्थान की यात्रा बने, न कि केवल प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की। निस्संदेह, ऐसे वक्त में जब कृषि से लेकर चिकित्सा तक और उत्पादन के क्षेत्र में एआई व रोबोटिक्स की दखल बढ़ रही है, प्रचुर श्रमशक्ति की उपलब्धता के बावजूद भारत को समय के साथ कदमताल करनी होगी। हमें एआई व रोबोटिक्स को अपनाना ही होगा। लेकिन सावधानी के साथ ताकि यह नौकरी खाने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बने। समय की पुकार है कि हम तकनीकी प्रगति को राष्ट्रीय संकल्प में बदलें। शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नैतिक नेतृत्व के सहारे भारत एआई युग में एक नई पहचान गढ़ सकता है। यदि हम चुनौतियों को स्वीकार कर दूरदर्शिता से आगे बढ़ें तो यह युग भारत के लिए केवल तकनीकी उन्नति का नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व और मानवीय पुनर्जागरण का युग सिद्ध हो सकता है। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से न्यायिक अधिकारियों को जोड़ने के सुप्रीम फैसले के राष्ट्रीय मायने

(कमलेश पांडे)

हालांकि इसको लेकर कुछ सार्वजनिक प्रभाव और चिंताएं दोनों हैं। यह ठीक है कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से दावों-आपत्तियों का निपटारा तेज होगा, और उनकी निर्णय अदालती आदेश माने जाएंगे। हालांकि, इससे नियमित अदालती कार्य प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता-पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग (ईसीआई) के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी। लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य-केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में एसआईआर विस्तार पर भी प्रभाव डाल सकता है, जहां समान विवाद हो सकते हैं। खास बात यह कि कोर्ट ने 'ट्रस्ट डेफिसिट' और 'ब्लेम गेम' की आलोचना की, जो संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देता है। हालांकि इसको लेकर कुछ सार्वजनिक प्रभाव और चिंताएं दोनों हैं। यह ठीक है कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से दावों-आपत्तियों का निपटारा तेज होगा, और उनकी निर्णय अदालती आदेश माने जाएंगे। हालांकि, इससे नियमित अदालती कार्य प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्वाचन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूत बनाता है, लेकिन राज्य सरकारों पर सहयोग न करने का दबाव बढ़ाता है। यूँ तो इस फैसले से अन्य राज्यों पर सीधा कानूनी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पश्चिम बंगाल की असाधारण परिस्थितियों (ट्रस्ट डेफिसिट और ब्लेम गेम) तक सीमित रखा। लेकिन जहां तक अन्य राज्यों में एसआईआर स्थिति का सवाल है तो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां एसआईआर पहले ही चल रहा था या विवादास्पद रहा, वहां बंगाल जैसी न्यायिक हस्तक्षेप की कोई तत्काल मांग नहीं दिख रही। वहीं 12 राज्यों (यूपी, बंगाल सहित) में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ चुकी, फॉर्म वितरण 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

जहां तक इस फैसले के संभावित प्रभाव की बात है तो यह फैसला अन्य राज्यों के लिए पूर्वाधार बन सकता है, जहां राज्य-ईसीआई विवाद बढ़े तो न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का विकल्प खुले। चूंकि कोर्ट ने असाधारण कदम उठाने पर जोर दिया, जो पारदर्शिता बढ़ाएगा लेकिन नियमित अदालती कार्य प्रभावित कर सकता है। फिर भी कोर्ट का यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट निर्णय/फैसला राज्य सरकारों को केंद्रीय संस्थाओं से सहयोग बढ़ाने का संदेश देता है, वरना समान निर्देश संभव है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती की संभावना मजबूत दिख रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। इसलिए एसआईआर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा पर विचार कर रहा है, क्योंकि प्रक्रिया में हिंसा, बीएलओ धमकियां और विवाद बढ़े हैं। पुलिस तैनाती की बात कही, और ईसीआई के पास राज्य पुलिस न मानने पर सेंट्रल फोर्स लेने का अधिकार है। इसलिए मार्च में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद तनाव बढ़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती तय मानी जा रही, जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगी। विपक्ष इसे जरूरी बता रहा, जबकि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर भरोसा जताती है, लेकिन ईसीआई अंतिम फैसला लेगा। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जाति संघर्ष का सर्वसमावेशी समाधान वक्त की जरूरत

पिछड़ों को आरक्षण को समाज ने स्वीकार कर लिया था, तभी दूसरे सवर्ण और मनमोहन सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने साल 2006 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की शुरूआत कर दी। इसके विरोध में एक बार फिर युवा राजनीति उभरी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा-निर्देशों से ना सिर्फ जाति विमर्श केंद्र में आ गया है, बल्कि हिंदू समाज जातीय खांचे में बंटता नजर आ रहा है। आर्थिक और शैक्षिक विकास की वजह से जाति विभाजन की जो रेखाएं मध्यम पड़ने लगी थीं, वे एक बार फिर गहरी होती नजर आ रही है।

(उमेश चतुर्वेदी)

मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जैसा स्पष्ट विभाजन हिंदू समाज में दिख रहा था, कुछ उसी राह पर एक बार फिर समाज बढ़ता दिख रहा है। जाति के तवे पर राजनीतिक रोटी सेंकने वाले कुछ दल यूजीसी की गाइडलाइन को लागू करने के लिए छात्रों के बीच जाति विमर्श की आंच को हवा दे रहे हैं तो इस गाइडलाइन के विरोध में खड़े सवर्ण समाज के लोग भी अपने समाज के छात्रों को लामबंद करने में प्राणपण से जुटे हुए हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह नया राजनीतिक विमर्श खड़ा हुआ, जिससे कुछ राजनीतिक दलों और शख्सियतों को उभरने का मौका मिला, कुछ वैसे ही हालात एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। अगर यूजीसी गाइडलाइन का सर्वसमावेशी हल नहीं खोजा गया तो हिंदुत्व की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। हिंदू एकता का सपना भी खतरे में पड़ सकता है।

राजनीति के बारे में एक धारणा है। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास ने जाति विभाजन को जहां कमजोर किया, वहीं राजनीति इसे जिंदा करने में सफल हुई है। सामाजिक यात्रा में पिछड़ी रह गई जातियों के उत्थान के नाम पर राजनीति ने जाति विमर्श को केंद्र में लाने का सबसे बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है, जिन्होंने देवीलाल के राजनीतिक रसूख को काबू में करने के लिए 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर पड़ी धूल को झाड़ा और उसे लागू कर दिया। पैंतीस साल पहले के उस फैसले ने समाज को बुरी तरह विभाजित कर दिया। मंडल आयोग के खिलाफ तकरीबन समूचा उत्तर भारत धधक उठा था। सवर्ण समुदाय के छात्रों और नौजवानों को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था। उन्होंने खुद को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह कविता भी करते थे। कवि को लेकर धारणा है है कि वह कोमल हृदय का स्वामी होता है। लेकिन आग की लपटों के बीच धू-धूकर जवानी को जलती देखकर भी कवि हृदय प्रधान मंत्री नहीं पसीजे थे। उस दौर के शरद यादव सवर्ण समाज के कटु आलोचक और पिछड़ावादी राजनीति के प्रबल पैरोकार के रूप में उभरे। मंडल आयोग की रिपोर्ट से समाज के बीच जो खाई पैदा हुई, बाद की राजनीति ने उसे और ज्यादा चौड़ा और गहरा ही किया है।

पिछड़ों को आरक्षण को समाज ने स्वीकार कर लिया था, तभी दूसरे सवर्ण और मनमोहन सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने साल 2006 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की शुरूआत कर दी। इसके विरोध में एक बार फिर युवा राजनीति उभरी। यूथ फॉर इक्वलिटी के बैनर तले दिल्ली में इस फैसले के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर पड़े। इस आंदोलन के चलते भी सामाजिक विभाजन बढ़ा। शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण के विरोधी समुदायों और इसके समर्थक समुदायों के बीच एक बार फिर विभाजक रेखा गहरी हुई। इससे भी देश उबर रहा था कि यूजीसी की गाइडलाइन आ गई और फिर से एक बार भारतीय समाज गहरे अंतरद्वंद्व और सामाजिक संघर्ष से जूझने लगा। यह संघर्ष अभी समाज में सीधे तो नहीं दिख रहा, लेकिन विश्वविद्यालयों के परिसर इसके चलते उबल रहे हैं। एक तरफ इस गाइडलाइन के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ उसके विरोधी।

आज पिछड़ावाद, दलितवाद, अल्पसंख्यकवाद और महिलावाद का जोर है। इन तबकों के उभार के विचार को सामाजिक न्याय करीब साढ़े तीन दशकों से स्वीकार किया जा रहा है। इन वादों को सामाजिक लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फीयर के केंद्र में लाने का विचार समाजवादी राजनीतिक दलों का रहा है, लेकिन इसे मूर्त रूप में लाने वाले कांग्रेसी मूल के राजनेता ही रहे हैं। समाजवादी दलों के ही परोक्ष समर्थन से पहली बार तीस मई 1933 को बिहार के मौजूदा रोहतास जिले के करगहर में त्रिवेणी संघ की स्थापना हुई थी। जिसमें कोइरी यानी कुशवाहा, कुर्मी और यादव जातियों के नेता साथ आए थे और पिछड़ावादी राजनीति की नींव डाली थी। एक तरह से जातिवादी राजनीति की नींव आजादी के पहले ही पड़ गई थी। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह भले ही जनता दल नामक समाजवादी विचारधारा वाले दल के नेता थे, लेकिन महज तीन साल पहले तक वे कांग्रेसी थे। अर्जुन सिंह भी कांग्रेसी ही थे। आज राहुल गांधी भी जाति जनगणना को लेकर

उत्साहित नजर आते हैं। पता नहीं राहुल गांधी को पता है या नहीं, अर्जुन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जानकारी जरूर रही होगी। राहुल गांधी की दादी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों के नाम तीस पैराग्राफ का एक लंबा खत लिखा था। उसके चौबीसवें से छब्बीसवें पैरे में नेहरू ने आज की जाति आधारित आरक्षण को एक तरह से नकार दिया है। उस चिट्ठी में उन्होंने भारत को बनाने को लेकर उनकी जो सोच रही, उसका गहन जिक्र किया है। इस पत्र में नेहरू स्पष्ट रूप से अपने विचार को जाहिर करते हैं। वे आरक्षण आधारित विकास और समाज नहीं चाहते थे, बल्कि ज्ञान केंद्रित समाज का विकास चाहते थे। नेहरू के लिखा था, मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खासकर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अक्षमता को बढ़ावा देता है और हमें औसत दर्जे की ओर ले जाता है।

यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे लोग अगर आज यही बात कहें तो उन्हें सामाजिक न्याय का विरोधी माना जाएगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से जिस तरह का राजनीतिक विमर्श स्थापित हुआ, उसमें सवर्ण समाज अपने लोगों के विकास और आरक्षण विरोध की बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। ऐसा करने से उसे दकियानूस माने जाने का खतरा नजर आता था। इसलिए उसने चुप्पी साधे रखी। लेकिन बाद के वर्षों में एससी-एसटी कानून का सवर्ण समाज के खिलाफ जारी दुरूपयोग ने सामाजिक रूप से आगे माने जाते रहे वर्णों और जातियों को मौका मिला। बाढ़ का पानी जब नाक तक पहुंच जाता था, तब व्यक्ति उससे बचाव के लिए छटपटाने लगता है। सवर्ण समाज के लिए यूजीसी की गाइडलाइन नाक तक पहुंचा बाढ़ का पानी है। उसी पानी से बचाव की छटपटाहट ही है कि गाइडलाइन के खिलाफ समूचे देश के सवर्ण समाज में गहन क्षोभ और गुस्सा नजर आ रहा है। अब सवर्ण समुदाय के नौजवान तर्क देने से हिचक नहीं रहे कि जब पिछड़ावाद हो सकता है, दलितवाद प्रगतिशील विचार हो सकता है, अल्पसंख्यकवाद सामाजिक न्याय का प्रतीक हो सकता है तो ब्राह्मणवाद या सवर्णवाद दकियानूस क्यों? सवर्ण समुदाय के बच्चों का कहना है कि माना कि उनके पूर्वजों ने गलती की तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें। ध्यान देने की बात है कि राममंदिर आंदोलन के बाद सवर्ण समाज ने पूरी तरह बीजेपी का दामन थाम लिया। उसे बीजेपी में अपनी दबी भावनाओं की अभिव्यक्ति की राह दिखती रही है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन से वह भौंचक्क रह गया। यही भौंचक्कापन अब गुस्से के रूप में नजर आ रहा है। सत्ता पर निगाह जमाए बैठे विपक्षी दल पर्दे के पीछे से इस गुस्से को हवा दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें पिछड़ा वोटर के बिदकने का खतरा भी नजर आ रहा है, इसी सोच के चलते वे गाइडलाइन के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं।

ऐसा नहीं कि बीजेपी में इस आफत की काट नहीं खोजी जा रही होगी। बीजेपी संगठन और सरकार के आलानेता इस जातीय विमर्श को ठंडा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने में जितनी देर होगी, जाति विमर्श उतना ही बढ़ेगा। अगर सवर्ण समुदाय का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

होली के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग रहेंगे अलर्ट मोड़ में, घूमेगी पेट्रोलिंग गाड़ियां, हॉस्पिटल में रहेंगे डॉक्टर और उनकी टीम

सड़क रोककर जबरन चंदा वसूली जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित

नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

डामरीकरण हुए पक्की सड़कों पर होलिका दहन प्रतिबंधित

परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति के डीजे बजाने पर रोक

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक सम्पन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

आगामी होली और रमजान पर्व को शांतिपूर्ण एवं सदभाव वातावरण में मनाने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के सदस्य, पत्रकारगण उपस्थित रहे।बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि होली के दौरान कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में वाहन न चलाए तथा शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने त्योहार के दौरान अभद्र व्यवहार न करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की।

होलिका दहन केवल निर्धारित समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। डामरीकरण (पक्की) सड़कों पर होलिका दहन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि सड़कों को नुकसान न पहुंचे। इस वर्ष होलिका दहन 2 तारीख की रात्रि में किया जाएगा। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति के डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे, ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल कर सहायता लेने की अपील की गई है।कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि शांति समिति की बैठक का उद्देश्य समाज और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि जिले में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। उन्होंने जिलेवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ पर्व मनाएं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सड़क रोककर जबरन चंदा वसूली जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित है, ऐसा न हों। आमजन एवं महिलाओं को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही किसी को जबरदस्ती गुलाल न लगाने और शासकीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली और रमजान दोनों महत्वपूर्ण पर्व हैं, जिन्हें आपसी सद्भाव और शांति के साथ मनाना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

रायगढ़ जिला के लैलूंगा विकास खंड अंतर्गत प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोड़ासिया मे छात्रावास मे रहने वाले बच्चे कर रहे है मजदूरी

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ जिला के लैलूंगा विकास खंड अंतर्गत प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोड़ासिया मे छात्रावास मे रहने वाले बच्चे कर रहे है मजदूरी, बच्चियां खतरों से खेलते हुवे किचन, बावन्ड्री वाल पुरे परिसर की पोताई करते हुवे नजर आ रहे है। शिक्षा विभाग से आदिवासी विभाग मे सलग्न प्रभारी छात्रावास अधीक्षक श्रीमती पूर्णिमा चौहान द्वारा रहवासी बच्चों को लिपाई पोताई कराते हुवे मजदूर के तर्ज पर काम कराया जा रहा है और बोला जाता है की स्कुल घर या कहीं भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है की यहाँ छोटी मोटी काम करते हो। काम करना से बच्चों की मानसिकता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और साथ ही बच्चे यहाँ अपने भविष्य बनाने के मनसा लेकर शासन के करोड़ो का फण्ड के साथ छात्रावास मे अच्छे खान-पान, रहन- सहन अच्छा वातावरण

अनुकूल मे पढ़ाई करने के लिये आते है और यहाँ शासन के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी द्वारा बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है।प्रभारी अधीक्षक पूर्णिमा चौहान इसी वर्ष 26 जनवरी 2026 को अच्छे कार्य करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रसस्ती पत्र प्रदान किया गया है लेकिन धरातल मे बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है

शासन द्वारा बच्चो को किसी प्रकार से परेशानी ना हो इसके लिये लाखो का फण्ड,सेवा हेतु पर्याप्त कर्मचारी एवं प्रत्येक छात्रावास मे 2 रसोइया 1 चौकीदार तथा 1 अधीक्षक रखा है तथा प्रति 1 या 2 वर्ष मे शासन द्वारा लिपाई पोताई एवं अन्य मरम्मत कार्य के लिये 20 से 25 हजार राशि प्रदान किया जाता है,राशि आहरण करने के बावजूद बच्चो को काम कराया जा रहा है तथा आदिवासी बच्चों के पढ़ाई लिखाई एवं जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है।उनके पढ़ने लिखने के समय को कटौती कर काम कराना दुर्भाग्य है ।

छात्रावास अधीक्षक आखिर किसके संरक्षण मे नियम विरुद्ध बच्चो से काम करा रहे है? क्या आज तक जिला अधिकारियो को इसकी सुचना प्राप्त नहीं हुई है? क्या चंद रूपये बचाने के लिये से विभागीय जिलाधिकारी से सांठ गांठ मे ऐसा खेल खेला जा रहा है? क्या शासन लिपाई पोताई के लिये फण्ड राशि नहीं देता? इस तरह बच्चो से काम कराने से छात्रावास अधीक्षक के ऊपर अनेक सवाल खड़े होते है। अब देखना यह है की समाचार प्रकाशित होने पश्चात मे विभाग द्वारा दोषी अधीक्षक को खाना पूर्ति कर अभयदान दिया जायेगा या उचित कार्यवाही करते हुवे मूल पदस्थापना वापिस किया जायेगा।

अध्यक्ष उदय भानु चिब की जमानत पर पीएम मोदी एवं अमित शाह की दमनकारी कार्यवाही की घोर निंदा

जशपुरनगर/मूक पत्रिका

केंद्र की तानाशाही सरकार द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की जमानत पर पीएम नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की दमनकारी कार्यवाही की घोर निंदा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चि को भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन (शर्टलेस प्रोटेस्ट) करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसका यूथ कोंग्रेसियों ने पुरजोर विरोध किया है युवा कांग्रेस के जिला महासचिव जयन्त लकड़ा ने बगीचा में हुए पुतले दहन का समर्थन किया।जयन्त ने कहा की यह गिरफ्तारी मात्र एक दिखावा थी, जिसका उद्देश्य युवा आवाज को दबाना और असहमति को कुचलना था।पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा श्री उदय भानु चिब जी को सश जमानत प्रदान किए जाने के बावजूद, हम देख रहे हैं कि नरेंद मोदी की सरकार और उनकी पुलिस मशीनरी लगातार युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाए हुए है। यह जमानत कोई राहत नहीं, बल्कि एक और साजिश का हिस्सा है–जिसमें पासपोर्ट सरेंडर, डिवाइस जमा करने जैसी शर्तें थोपकर युवा नेतृत्व को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। युवा कांग्रेस के जिला महासचिव जयन्त लकड़ा की ओर से, नरेंदर मोदी और अमित शाह जी की इस दमनकारी, तानाशाही और लोकतंत्र-विरोधी कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हैं। यह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार असहमति सहन नहीं कर पा रही है। जब युवा सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो उन्हें जेल भेजा जाता है, जबकि भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोपों पर चुप्पी साध ली जाती है।हम मांग करते हैं:उदय भानु चिब जी के खिलाफ लगाए गए सभी फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए।जयन्त लकड़ा ने कहा भारतीय युवा कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा–चाहे जितनी भी गिरफ्तारियां हों, जमानत की शर्तें थोपी जाएं। सत्य की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी।

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग की विस्तृत बैठक ली

मुंगेली/मूक पत्रिका

जिले में संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग की विस्तृत बैठक ली। बैठक में स्कूल एवं महाविद्यालय सहित अन्य भवनों के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्कूल एवं महाविद्यालय भवनों का निर्माण समय पर नहीं होना गंभीर लापरवाही है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ नहीं करने एवं संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने पर कार्यपालन अभियंता (ईई), एसडीओ मुंगेली एवं सब इंजीनियर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सब इंजीनियर सूर्य प्रकाश राजपूत का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए। गोड़खाम्ही में भवन निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि कार्य समय पर पूर्ण होते तो विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल पाता। बैठक में प्रगतिरत सड़क निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने प्रशासकीय स्वीकृति, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य पूर्णता की स्थिति की जानकारी ली। जिन सड़कों का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके कारणों की जानकारी लेते हुए संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग चैड़ीकरण, बोधापारा-बोड़तरा मार्ग चैड़ीकरण, सरगांव से साकेत मार्ग मजबूतीकरण, बंधवा पुल से गोड़खाम्ही पहुंच मार्ग, मुंगेली से परसवारा, हरदी से भस्करा पहुंच मार्ग, कंतेली-सूरजपुरा-डिंडौरी-कोयलारी मार्ग, सरईपतेरा-हरदीबांध-उरईकछार तथा पथरी से डिंडोरी पहुंच मार्ग सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग टूल विकसित किए जाएं तथा नियमित निरीक्षण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने दोहराया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं।

14 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय तक के सभी न्यायालयों में वर्ष 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में सबंधित व्यक्ति माननीय न्यायालय, राजस्व विभाग के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माननीय न्यायालय, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, समस्त बैंको आदि से संपर्क कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए निराकरण किया जाएगा।

ट्रिपल आईटी में 17 - 18 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन

प्रत्येक विषय-धारा में चयनित युवा वैज्ञानिक को 21 हजार रूपए का नकद पुरस्कार

सारंगढ़ बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को शोध, नवाचार और अकादमिक पहचान का सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 21वां छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन (सीवायएससी - 2026) का आयोजन 17 एवं 18 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा ट्रिपल आईटी नया रायपुर द्वारा किया जा रहा है। सीवायएससी - 2026, छत्तीसगढ़ के उभरते हुए युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शोध अनुभव तथा वैज्ञानिक समुदाय में पहचान प्राप्त होगी। यह सम्मेलन राज्य की विकास आवश्यकताओं से जुड़े मौलिक, नवोन्मेषी एवं गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. कवीश्वर प्रशांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन राज्य की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। सीवायएससी 2026 के माध्यम से राज्य में हो रहे मौलिक एवं नवाचारी शोध को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान किया जाएगा। सीवायएससी - 2026 के प्रत्येक विषय-धारा में चयनित युवा वैज्ञानिक को 21 हजार रूपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

जिला शिक्षाधिकारी श्री जीआर मंडावी का औचक निरीक्षण, कोंटा-मरईगुड़ा के परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की ली जानकारी

सुकमा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा 2026 के अंतर्गत कोंटा एवं मरईगुड़ा क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जिला शिक्षाधिकारी श्री जी.आर. मंडावी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती पाई गई।जिला शिक्षाधिकारी ने शासकीय अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा तथा शासकीय हाई स्कूल मरईगुड़ा (वन) में कक्षा 10वीं के परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।इस दौरान मरईगुड़ा में संचालित पोर्टाकेबिन एवं आश्रमशाला का भी निरीक्षण किया गया। यहां विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था, अध्यापन कार्य तथा परीक्षा की तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला शिक्षाधिकारी ने बच्चों की सुविधाओं और शैक्षणिक वातावरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्राथमिक विद्यालय नुलकातोंग एवं माध्यमिक शाला नुलकातोंग का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका शैक्षणिक स्तर परखा। बच्चों ने उत्साहपूर्वक पहाड़े और गिनती सुनाकर अपनी तैयारी का परिचय दिया। बैगलेस डे के अवसर पर विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण विषय पर संस्था प्रमुख एवं स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। सभी शिक्षण संस्थानों में मध्यान्ह भोजन योजना सुचारू रूप से संचालित पाई गई। विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं तथा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित रूप से कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान संस्थान में 5 शिक्षक उपस्थित थे, जबकि एक शिक्षक अवकाश पर थीं। इस अवसर पर बीईओ कोंटा भी उपस्थित थे।

रायपुर के लिए रवाना हुए बीजापुर के तीरंदाज, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले के युवा तीरंदाज सातवीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रायपुर रवाना हो गए हैं। यह प्रतियोगिता खेलो इंडिया के अंतर्गत रायपुर ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। टीम के रवाना होते समय खिलाड़ियों में उत्साह और आत्मविश्वास दोनों नजर आए।बीजापुर की टीम कोच दुर्गेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। पिछले कुछ दिनों से खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे थे और अब राज्य स्तर पर अपने प्रदर्शन को साबित करने के लिए तैयार हैं। अंडर-15 रिकर्व राउंड में बीजू कुर्सम और सरिता तेलम हिस्सा लेंगे। इंडियन राउंड में सुशीला हेमला, रोनी हेमला और उर्मिला उर्सा अपना कौशल दिखाएंगी। बालक वर्ग में अजय कुड़ियम, कृष्णा धुर्वा और संतोष सोयम जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर-13 में पायल कचलाम और अंडर-10 वर्ग में आर्शी करनेवार प्रतियोगिता में भाग लेंगी।कलेक्टर संबित मिश्रा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिले के कोच भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अब जिलेवासियों की उम्मीद इन युवा तीरंदाजों पर टिकी है कि वे राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर बीजापुर का नाम रोशन करेंगे।

बेमेतरा में मां भद्रकाली जिला मानस संघ की आवश्यक बैठक 1 मार्च को

बेमेतरा। मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के तत्वावधान में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यानमाला प्रतियोगिता 2026 के सफल आयोजन की समीक्षा एवं होली मिलन कार्यक्रम की योजना को लेकर 1 मार्च , रविवार को संघ की महत्वपूर्ण बैठक प्रातः 10:30 बजे बेमेतरा स्थित किसान भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी, सभी तहसील अध्यक्ष–बेमेतरा, नवागढ़, बेरला एवं साजा तथा समस्त पंजीकृत मानस मंडलियों सहित सभी मानस प्रेमी की उपस्थिति अपेक्षित है।संघ के अध्यक्ष श्री देवलाल सिन्हा ने बताया कि बैठक में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही होली मिलन के माध्यम से आपसी समन्वय और सांस्कृतिक एकता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

हवन पूजन के साथ हुआ संपन्न

गायत्री शक्तिपीठ बीजापुर का दसवां प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव कलश यात्रा

बीजापुर/मूक पत्रिका

बीजापुर नगर के हृदय स्थल में चेतना के केंद्र के रूप में बने गायत्री शक्तिपीठ का वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के अनेक ग्रामों में संस्कारों की परिपाटी को जीवन एवं जागृत करने के लिए गायत्री परिवार का यह मंदिर वर्ष 2016 में बना था जिसका दसवां प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम दिनांक 26 से 28 फरवरी में संपन्न हुआ । गायत्री शक्तिपीठ में विराजित माता गायत्री माता दुर्गा एवं माता सरस्वती का गर्भगृह में विधि विधान से प्रातः कालीन शुभ मुहूर्त में विशेष पूजन किया गया तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं वंदनीया माता भगवती देवी शर्मा के सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा में गुरु पूजन किया गया। 10:00 बजे से पांच कुण्डीय गायत्री महायज्ञ के में लोक कल्याण के लिए आहुतियां समर्पित की गई एवं आए हुए जिले के माता, बहनों,भाइयों ने कार्यक्रम में भागीदारी कर कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रथम दिवस 12 घंटे का गायत्री मंत्र का खंड जब प्रातः 6:00 से संध्या 6:00 बजे तक किया गया संध्या 7:00 बजे से सुंदरकांड रामायण पाठ का आयोजन मां दंतेश्वरी मानस मंडली एवं गायत्री परिवार के द्वारा किया गया। द्वितीय दिवस माता-पिता दिवस मनाया गया जहां पर बच्चों को अपने माता-पिता की सेवा एवं महत्व को दर्शन दर्शाता हुआ संस्कार जागरण का कार्यक्रम पूरा किया गया ।संध्या 5:00 बजे से नगर में माता बहिनों द्वारा मंगल कलश सर पर धारण कर नगर में कलश यात्रा निकाली गई और प्रज्ञा गीतों प्रज्ञा नारों एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण से नगर में भक्तिमय वातावरण का निर्माण किया गया । कलश यात्रा उपरांत आरती एवं दीपयज्ञ में भावनात्मक आहुतियां समर्पित की गई। कार्यक्रम में 11 दीक्षा संस्कार एवं एक अन्नप्राशन संस्कार तथा एक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। पूर्णाहुति उपरांत आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए शक्तिपीठ में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी गई थी जिसे सभी ने ग्रहण किया । कार्यक्रम का संचालन जगदलपुर के वर्तमान परिव्राजक अच्छे लाल साहू जी के द्वारा सुंदर भजन कीर्तन प्रज्ञा संगीत और कार्यकांड द्वारा युग निर्माण सृजन में आज के मानव की भागीदारी के महत्व को बताते हुए समयदान अंशदान व्यक्ति निर्माण परिवार निर्माण के सूत्रों को समझाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्रबन्ध ट्रस्टी शंकर कुड़ियम,जिला समन्वयक बीरा राजबाबू वरिष्ठ परिजन विजय बहादुर राजभर व्यवस्थापक जयपाल सिंह राजपूत लेखा प्रभारी बैजनाथ गुप्ता, राहुल गुप्ता,अर्जुन वेको, रुक्मणी झाड़ी, अर्चना सिंह, रामयश विश्वकर्मा, मोहिनी साहू, गायत्री मरकाम, सहदे वाचम,महेश, दुर्गा वाचम , संतोष अग्गीवार, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के संतोष, बुछैया पुजारी, कमला पुजारी, मंजू पुजारी, गारा लालैया, सरिता पसपुल, नमिता पसपुल, मनीष राजभर, नीला पेरमा, रामैया लम्बाड़ी, सुनील साहू, धनोज साहू, प्यारेलाल आदि अनेक परिजनों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया।

● क्यों लिया गया फैसला

लोन के गारंटर की भी अब बढ़ेगी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश

नईदिल्ली, एजेंसी। यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ दायर अपीलों के एक समूह के बाद आया है। डिफॉल्ट की स्थिति में कर्ज लेने वाले और इसके गारंटर, दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एक ही कर्ज के लिए मूल कर्जदार और उसके कॉरपोरेट गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ दिवाला कार्यवाही चलाई जा सकती है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है जो वित्तीय कर्जदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए समानांतर कार्रवाई शुरू करने से रोकता हो। इस फैसले ने भारतीय अनुबंध अधिनियम के उस मूलभूत सिद्धांत की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि जमानतदार (गारंटर) का दायित्व मूल कर्जदार के दायित्व के बराबर होता है। इसमें कहा गया कि यदि किसी कर्जदाता को एक दिवाला प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरी शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो गारंटी का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। फैसले में कहा गया कि इसका मतलब यह होगा कि अंतरिम अवधि में गारंटर को ऋण चुकाने से छूट मिल जाएगी, जिसका प्रावधान आईबीसी में नहीं है। यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ दायर अपीलों के एक समूह के बाद आया है। इसने आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की उन अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिनमें पहले गारंटरों के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोक दी गई थी। इसने कंपनियों के निदेशकों की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने अपनी कंपनियों के खिलाफ समानांतर कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था। इस फैसले में आवेदनों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें कहा गया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को प्रत्येक आवेदन की योग्यता के आधार पर जांच करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि ऋणदाता संहिता के तहत अनुमत उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

क्या कहा गया है फैसले में

न्यायमूर्ति दत्ता ने 47 पृष्ठ के फैसले की शुरुआत में लिखा कि न्यायाधीश को मनमाने ढंग से नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा– ऋणदाता द्वारा अपने कर्ज के लिए गारंटी प्राप्त करने के औचित्य को पूरी तरह से समझना उचित जान पड़ता है। आईबीसी के अंतर्गत अधिकारों से संपन्न वित्तीय ऋणदाता को इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसी प्रकार, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह आवेदन की स्वतंत्र रूप से, उसके गुणों के आधार पर जांच करे।

मोदी सरकार बांट रही क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से है लिंक्ड

नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड दिया जता है। ऐसी ही एक योजना- पीएम स्वनिधि है। इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट कार्ड देती है। आइए योजना की डिटेल जान लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना

की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी। योजना का मकसद महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय संकटों से उबरने तथा प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने में रेहड़ीङ्कपटरी विक्रेताओं की सहायता करना था। बता दें कि योजना की ऋण अवधि 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ है। पुनर्गठित योजना के अंतर्गत 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले चरण में पहले 10 हजार रुपये का लोन दिया जाता था लेकिन अब लोन की रकम को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। वहीं, दूसरे चरण का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 जबकि तीसरे चरण में लोन की राशि को बाकर 50,000 किया गया है। यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को अचानक सामने आने वाली व्यावसाय से जुी अथवा व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए तत्काल ऋण सुविधा प्रदान करेगा। नियमित बिक्री पर अधिकतम 1,200 तक का कैशबैक मिलता है। वहीं, 2000 या उससे अधिक की थोक खरीद पर अधिकतम 400 तक का कैशबैक मिलता है।

जिस बैंक में गए वापस लौटे खाली हाथ, फिर कुछ ऐसा किया काम कि अब 90 लाख रुपये का टर्नओवर

नई दिल्ली, एजेंसी। शंकर मीणा राजस्थान के एग्रीप्रेन्योर हैं। वह जीवन मशरूम के मालिक हैं। जीवन मशरूम कई तरह के मशरूम बनाती है। इनमें बटन, ऑयस्टर, लायन मेन, पैडी स्ट्रॉ, शिटाके, गैनोडर्मा और पोर्टोबेलो शामिल हैं। शुरू में उन्हें हर एक बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। आज अपने वेंचर से वह लाखों की कमाई कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 तक उनकी अपने वेंचर से सालाना कमाई लगभग 90 लाख रुपये पहुंच गई। आइए, यहां शंकर मीणा की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

शंकर मीणा का जन्म राजस्थान के जयपुर के पास दांतली के छोटे से गांव में हुआ। वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने पारंपरिक खेती की कमियों को देखा। लगातार कोशिश के बावजूद यह टिकाऊ इनकम देने में नाकाम साबित होती है।

उन्होंने गांव में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर बाद में कॉमर्स में बैचलर डिग्री हासिल करते हुए अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की। 2012 में उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए फुल-टाइम एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया। लेकिन, उन्हें जल्द ही पता चला कि करिकुलम उनके एंटरप्रेन्योरियल मकसद से मैच नहीं करता था। इस वजह से उन्होंने 2013 में दूसरे सेमेस्टर में ही पढ़ाई छोड़ दी। रोजगार के मौके तलाशने के बजाय शंकर मीणा का इरादा एक ऐसा बिजनेस बनाने का था जो लंबे समय तक रोजी-रोटी के मौके दे सके। जिसे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ा सकें। इस इरादे को एक्शन में बदलने के लिए शंकर ने जयपुर के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में डॉ. प्रदीप सिंह शेखावत से फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की। इस फेज ने उन्हें टेक्निकल जानकारी और बिजनेस क्लैरिटी दी, जो यह समझने के लिए जरूरी थी कि एग्रीकल्चरल वेंचर को बड़े पैमाने पर कैसे लॉन्च और मेनटेन किया जा सकता है। अपनी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाते हुए 2015 में वह एक वर्कशॉप में शामिल होने और मशरूम की खेती की बारीक बातों को समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन में ऑफ मशरूम रिसर्च गए।

एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में देखा बड़ा गैप

शंकर ने राजस्थान की एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में बड़ा स्ट्रक्चरल गैप देखा। राज्य में मशरूम स्पॉन प्रोडक्शन के लिए एक भी डेडिकेटेड यूनिट नहीं थी। इसकी वजह से किसान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। इस समस्या को पहचानने के बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने ड्डष्टक्रङ्कडायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, सोलन से मदर कल्चर लिया। अपने परिवार के इलेक्ट्रिकल बिजनेस से मिली कैपिटल का इस्तेमाल करके घर के गैरेज में टेम्पररी लैबोरेटरी बनाई। ट्रायल फेज में स्पॉन बिहेवियर, क्वालिटी कंट्रोल और छोटे लेवल पर

मुनाफे के बावजूद जैक डॉर्सी की कंपनी ने 4,000 कर्मचारियों को निकाला

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक इंटेलिजेंस टूल्स के बढ़ते प्रभाव ने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसी बदलाव का हवाला देते हुए, ट्विटर (अब एक्स) के सह-संस्थापक जैक डॉर्सी के नेतृत्व वाली वित्तीय तकनीकी कंपनी ब्लॉक ने अपने लगभग आधे कर्मचारियों की छंटनी करने का बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के इस कदम से 4,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। डॉर्सी ने इसे कंपनी के इतिहास के सबसे कठिन फैसलों में से एक बताया है।

मुनाफे के बावजूद छंटनी का फैसला क्यों

इस छंटनी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी किसी वित्तीय संकट से नहीं गुजर रही है। जैक डॉर्सी ने साफ किया है कि कंपनी का व्यवसाय मजबूत है, सकल लाभ लगातार बढ़ रहा है और मुनाफे में भी सुधार हो रहा है।

दरअसल, कंपनी द्वारा बनाए और इस्तेमाल किए जा रहे इंटेलिजेंस टूल्स ने काम करने के तरीके को बदल दिया है। इन टूल्स की मदद से छोटी टीमें

कैसे एआई बना फैसले का कारण

अधिक कुशलता और बेहतर तरीके से काम कर पा रही हैं। डॉर्सी का मानना है कि इस बदलाव को अपनाने में ब्लॉक ने कोई जल्दबाजी नहीं की है,

बल्कि ज्यादातर कंपनियां इस मामले में पिछड़ गई हैं। इस कटौती के बाद, कंपनी का आकार 10,000 से अधिक कर्मचारियों से घटकर 6,000 से भी कम रह जाएगा। कंपनी ने छंटनी का एलान करते हुए क्या-क्या कहा बार-बार होने वाली छंटनी से कर्मचारियों के मनोबल और ग्राहकों के भरोसे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए कंपनी ने एकमुश्त छंटनी का विकल्प चुना। निकाले गए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कंपनी ने एक मजबूत सेवरेंस पैकेज का ऐलान किया है-

प्रभावित कर्मचारियों को 20 सप्ताह का वेतन और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का वेतन दिया जाएगा। मई के अंत तक की वेस्टेड इक्विटी और छह महीने की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।

कर्मचारी अपने कॉरपोरेट डिवाइस अपने पास रख सकेंगे और ट्रांजिशन में मदद के लिए 5,000 डॉलर की अतिरिक्त राशि मिलेगी।

अमेरिका के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्थानीय नियमों के अनुसार समान सहायता प्रदान की जाएगी। अक्सर छंटनी के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का सिस्टम एक्सेस तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन ब्लॉक ने कर्मचारियों को ठीक से विदाई लेने का मौका देने के लिए गुरुवार शाम (पैसिफिक समय) तक स्लैक और ईमेल खुले रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, डॉर्सी एक लाइव वीडियो सेशन के जरिए कर्मचारियों को धन्यवाद भी देंगे। उनका मानना है कि कुशल और ठंडे रवैये की तुलना में यह अजीब लेकिन मानवीय तरीका अपनाना बेहतर है।

अब आगे क्या

वर्ष 2009 में स्क्वायर के रूप में शुरू हुई इस कंपनी ने 2021 में अपना नाम बदलकर ब्लॉक कर लिया था। 450 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। जो कर्मचारी कंपनी में रुक रहे हैं, उन्हें अब एक नई रणनीति पर काम करना होगा। डॉर्सी के अनुसार, भविष्य में कंपनी के हर काम और निर्माण के केंद्र में इंटेलिजेंस होगा, जिससे ग्राहक खुद कंपनी की क्षमताओं का उपयोग कर सीधे अपने लिए नए फीचर्स विकसित कर सकेंगे।

भारतीय कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी होगा आधुनिक, अडानी सीमेंट ने नारेडको से मिलाया हाथ

रियल एस्टेट के कामगारों को मिलेगा प्रशिक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्र निर्माण में बढ़ती कंस्ट्रक्शन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी सीमेंट ने नारेडको से एक समझौता किया है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल देश में रियल एस्टेट सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।

नारेडको और अडानी सीमेंट की तरफ से यहां जारी एक बयान के मुताबिक यह साझेदारी भारत की तेजी से बढ़ती निर्माण आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए है। इसके साथ ही 'विकसित भारत 2047' के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को योगदान देने के विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

बयान के मुताबिक यह साझेदारी देशभर में आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्ता, पर्यावरण अनुकूल उपायों और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले कामगारों यथा राजमिस्त्रियों और कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए संयुक्त रूप से कौशल विकास और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे इस सेक्टर के वर्कफोर्स आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा

मानकों और बदलते उद्योग मानकों से लैस हो सकेंगे।

बयान में बताया गया है ''यह सहयोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े नॉलेज साझा करने और तकनीक के आदान-प्रदान के लिए भी एक मंच का कार्य करेगा। इससे भारतीय कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एडवांस कंक्रीट सॉल्यूशन, नवोन्मेषी निर्माण पद्धतियों और आधुनिक निर्माण सामग्रियों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।'' क्या कहना है अडानी ग्रुप का अदानी ग्रुप में सीमेंट बिजनेस के सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, यह साझेदारीज. ऐसे परिवेश के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जहां गुणवत्ता, नवाचार और पर्यावरण अनुकूल पहल प्रत्येक परियोजना का अभिन्न हिस्सा हों।'' उन्होंने कहा, ''नारेडको के साथ मिलकर हम रियल एस्टेट कंपनियों को उन्नत सामग्री और गहन तकनीकी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, जिससे परियोजनाएं और बेहतर हो सके।'' नारेडको के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा, यह साझेदारी रियल एस्टेट और निर्माण परिवेश में पर्यावरण अनुकूल कदम और जिम्मेदार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दोनों इकाइयां साथ मिलकर हरित भवन मानकों को बढ़ावा देने, सहयोग को मजबूत करने और सतत विकास के लिए अधिक अनुकूल रूपरेखा तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगी।''

तेजस नेटवर्क्स का शेयर बना रॉकेट, 400 के पार पहुंचा दाम, मिला है बड़ा ऑर्डर

नईदिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को 8 प्रतिशत से अधिक के उछाल के साथ 403.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 2 दिन में 25 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स को जापान की कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को बीएसई क्रस्थ में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 403.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 2 दिन में 25 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स को जापान की कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 5 प्रतिशत मैसिव मिमो रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए है। हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर दो दिन में 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 25 फरवरी 2026 को 319.05 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को बीएसई में 403.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 36 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मार्केट कैप भी शुक्रवार 27 फरवरी को 7000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 44 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 फरवरी 2025 को 741.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को 403.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

● सरकार का प्लान है कि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए 90 दिनों तक का तेल भंडार रहे

90 दिनों का कोटा रहेगा पूरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्र मंथन करेगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। तेल के भंडार को लेकर सरकार अपना प्लान बदल रही है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार अब समुद्र मंथन करेगी। सरकार का प्लान है कि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए 90 दिनों तक का तेल भंडार रहे। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने तीन-स्तरीय रणनीति तैयार की है।

सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति में 6 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त रणनीतिक तेल भंडार बनाना, 'समुद्र मंथन' नाम से राष्ट्रीय गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन शुरू करना और देश को ग्लोबल रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित करना शामिल है। इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किए जा रहे हैं और मई-जून तक मंजूरी मिलने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 5.33 एमएमटी रणनीतिक कच्चा तेल भंडार है, का स्टॉक मिलाकर कुल भंडारण क्षमता करीब 80 दिनों की है।

जो करीब 10 दिनों के आयात के बराबर है। इसके अलावा ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पडुर में बन रहे वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक भंडार (करीब 11.83 एमएमटी, यानी 20-25 दिन) और रिफाइनरियों में मौजूद लगभग 55 दिन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 30 जून तक कैबिनेट से 6 एमएमटी अतिरिक्त भंडार बनाने की मंजूरी मांग सकता है। लक्ष्य 90 दिन का रणनीतिक तेल भंडार तैयार करना है।

सभी मौजूदा और आगामी एलएनजी टर्मिनलों के लिए 10 दिन का रणनीतिक गैस भंडार बनाने की योजना भी एजेंडे में है।

ऊर्जा सुरक्षा मिशन का दूसरा प्रमुख स्तंभ घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 'समुद्र मंथन' नाम से नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया जाएगा। मिशन के तहत 2026-27 से अगले पांच वर्षों में अन्वेषण कुओं की संख्या 30 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 100 प्रति वर्ष की जाएगी। इनमें हर साल 25 कुएं गहरे समुद्र क्षेत्रों में और 40 स्ट्रैटिग्राफिक कुएं शामिल होंगे। सरकार का तीसरा फोकस भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल हब बनाना है। लक्ष्य साल 2047 तक रिफाइनिंग क्षमता को 400 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाना है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स का मजबूत एकीकरण होगा।

विकसित भारत 2047 की यात्रा में महिलाएं केंद्रीय सूत्रधार, बोलीं डॉ प्रीति अदाणी

नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी, विकसित भारत सम्मेलन में महिलाओं को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का मुख्य आधार बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में उन्होंने जोर दिया कि वास्तविक सशक्तिकरण केवल एक संकल्पना नहीं है, बल्कि यह संसाधनों तक आसान पहुंच और महिलाओं की सतत आर्थिक भागीदारी से जुड़ा विषय है।

अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने भारत के विकसित भारत 2047 की यात्रा में महिलाओं को केंद्रीय सूत्रधार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने सशक्त नारी, विकसित भारत सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की आर्थिक क्षमता विकसित भारत की परिकल्पना का केंद्रबिंदु है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 26 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। डॉ. अदाणी ने महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत करते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास के पीछे की नीतिगत गति को स्वीकार किया। उन्होंने संकल्पना से आगे बढ़कर सतत आर्थिक भागीदारी की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने जोर दिया कि सशक्तिकरण की शुरुआत पहुंच से होती है। अदाणी समूह की सामाजिक कल्याण शाखा, फाउंडेशन की आरे से समर्थित पहलों के माध्यम से कृषि, डेयरी, स्वास्थ्य और उद्यम के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर परिणाम प्राप्त हुए हैं। सरल कृषि मोबाइल एप्लिकेशन से परिचित कराया गया है, जिससे उन्हें सिंचाई, उर्वरक उपयोग और मंडी मूल्य ट्रैकिंग में मार्गदर्शन मिलता है। इससे उच्च उत्पादकता और मजबूत आय प्राप्त हुई है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,500 से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष 75 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रहण करती हैं। पारदर्शी मूल्य निर्धारण और संगठित खरीद से उनकी आय स्थिरता बढ़ी है। फाउंडेशन की प्रमुख मातृ व महिला स्वास्थ्य पहल, सुपोषण के तहत प्रशिक्षित स्थानीय महिला स्वयंसेवकों ने 32 लाख से अधिक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार में सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, स्वाभिमान कार्यक्रम ने 300 उद्यम स्वयं सहायता समूहों में 4,500 से अधिक महिलाओं को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

सुजीत कलकल ने बढ़ाया भारत का मान

यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता

10-0 से राशिद को हराकर विजेता बने

नई दिल्ली। अंडर-23 विश्व चैंपियन सुजीत कलकल ने मुहामेट मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। 23 साल के भारतीय पहलवान ने फाइनल में अजरबैजान के राशिद बाबाजादे को 10-0 से हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जॉर्जिया के नीका जकाशविली को 10-0 से हराने और अल्बानिया के एंड्रियो अवदली पर 16-4 की जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करने के बाद सेमीफाइनल में अमेरिका के दो बार के पैन अमेरिकन चैंपियन जोसेफ मैककेना पर 11-0 से शानदार जीत हासिल की।

इस महीने की शुरुआत में क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन जीतने के बाद, यह 2026 यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में सुजीत का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। सुजीत ने एंड्रियो अवदली पर 16-4 से जीत के साथ वार्म अप किया, जिन्होंने बाउट की शुरुआत में भारतीय खिलाड़ी को चार अंक पर पटक दिया था। नीका जकाशविली (जॉर्जिया) अगले 10-0 से हार गए, इससे पहले सुजीत ने जोसेफ मैककेना (अमेरिका) को 11-0 से हराया, यह स्कोर जाग्रेब ओपन के सेमीफाइनल जैसा ही था। राशिद, जिन्होंने सेमीफाइनल में विटाली अरुजाउ (अमेरिका) के खिलाफ 16-13 से जीत हासिल की थी, वे फाइनल में मुकाबला नहीं कर पाए। सुजीत ने उन्हें 10-0 से हराकर लगातार दूसरा रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीता।

कुल मिलाकर, यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज सर्किट में सुजीत का चौथा स्वर्ण पदक था। इससे पहले उन्होंने 2022 जैहर शघायर और 2025 पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल में टॉप स्थान हासिल किया था। इसी कैटेगरी में हिस्सा ले रहे भारत के मोहित कुमार क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए।

57 किग्रा श्रेणी में अंकुश और आतिश टोडकर ने कांस्य पदक तक पहुंचने के लिए रेपेचेज में मुकाबला किया, लेकिन अपने-अपने मैचों में हार गए। इस बीच, सुमित (57 किग्रा), राहुल (61 किग्रा), सिद्धार्थ (70 किग्रा), परविंदर (74 किग्रा), और आर्यन (86 किग्रा) अपने-अपने वेट डिवीजन में मेडल राउंड तक पहुंचने में नाकाम रहे। भारत ने मुहामेट मालो 2026 के लिए 48 सदस्यों की कुश्ती टीम भेजी थी, जिसमें पुरुषों की फ्रीस्टाइल, महिलाओं की डिवीजन और ग्रीको-रोमन कैटेगरी में 16-16 लोग शामिल थे।

लॉस एंजिल्स ओलंपिक

बदले हुए वजन वर्ग में उतरेंगे पहलवान रवि दहिया

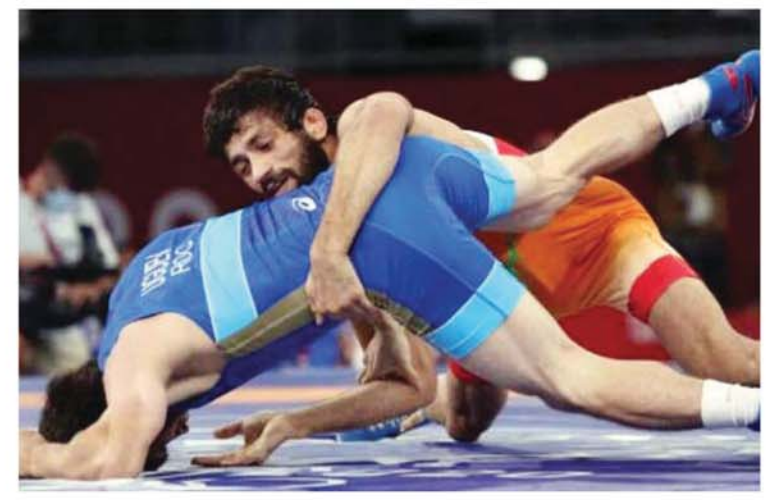

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया ने कहा है कि उनका लक्ष्य लॉस एंजिल्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है और इसके लिए वह तैयारी भी कर रहे हैं। टोक्यों ओलंपिक के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक विजेता रवि इसके बाद साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में वह जगह नहीं बना पाये और इसी कारण अब वह अपना भार वर्ग बदलकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं।

रवि 57 किग्रा की जगह अब 65 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा ले सकते हैं। उनसे देश को अगले ओलंपिक में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। इस खिलाड़ी का कहना है कि वह रजत तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। उनका लक्ष्य स्वर्ण जीतना है। रवि को पहचान 2018 में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में मिली। तब 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं साल 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की थी। रवि एशियाई चैंपियनशिप में भी विजेता हैं। 2018, 2020, और 2021 में उन्होंने इसमे स्वर्ण पदक जीते थे।टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने साल 2022 में राष्ट्रमण्डल खेलों में भी दहिया ने स्वर्ण पदक जीता था।उनके पिता राकेश दहिया तो किसान हैं, लेकिन उनके चाचा मुकेश दहिया कुश्ती से जुड़े रहे हैं। इस वजह से रवि को कुश्ती विरासत में मिली है, जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से सफल बनाया है। रवि ने केवल 10 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती प्रशिक्षण के लिए दाखिला लिया।

हम विरोधी गेंदबाजों में डर देखना चाहते थे : तिलक

चेन्नई। भारतीय टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में टीम तय करके उतरी थी कि शुरुआत से ही विरोधी टीम पर दबाव बनाया जाये। तिलक के अनुसार हमारी टीम चाहती थी कि विरोध गेंदबाजों के अंदर डर का माहौल बने। जिससे कि वह सटीक गेंदबाजी नह कर पायें। भारतीय टीम ने चेन्नई में हुए इस सुपर-8 मैच में 256 रन बनाकर जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। तिलक ने कहा, हम टीम के रूप में अच्छा स्कोर बनाना चाहते थे। हमने इस पर बात की थी कि अगर हम पावर प्ले में तीन या चार विकेट भी गंवा दें तब भी आक्रामक होकर ही खेलेंगे। तिलक ने संजू सैमसन की पारी की भी सराहना की। सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए 15 गेंद पर 24 रन बनाए और अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 3.4 ओवरों में ही 48 रनों की साझेदारी बनायी। तिलक ने कहा, जब सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देते हैं तो इससे तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के बल्लेबाजों का भी मनोबल बढ़ता है। सैमसन ने अच्छी शुरुआत की। इसके बाद हम विरोधी गेंदबाजों के अंदर डर देखना चाहते थे। और तिलक ने कहा कि खिलाड़ियों ने चेपॉक में खेले गए मैच से पहले पिछले टी20 मैचों के वीडियो देखे। उन्होंने कहा, हमने मैच से ठीक पहले बात की थी कि हम सकारात्मक मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे। हमने पिछले एक साल में टी20 क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन वीडियो को देखने के बाद हम सभी का मनोबल बढ़ा। तिलक ने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी टीम के सदस्यों को बिना किसी दबाव के अपना स्वाभाविक खेल खेलने को कहा था। उन्होंने कहा, कोच कहा था कि हालात चाहे कैसी भी हो, बस उस तरह की क्रिकेट को याद रखें जो हमने पिछले साल से तथा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीजमें खेली थी।

एएफसी महिला एशियन कप फुटबॉल में अच्छे प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

भारतीय टीम को ग्रुप सी में वियतनाम, जापान और चीनी ताइपे के रखा गया

नई दिल्ली। भारतीय टीम अगले माह की शुरुआत में होने वाली एएफसी महिला एशियन कप फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन कर फीफा महिला विश्व कप में प्रवेश के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने उतरेगी। भारतीय टीम को एशियन कप के ग्रुप सी में वियतनाम, जापान और चीनी ताइपे के रखा गया । उसे 4 मार्च को वियतनाम, 7 को जापान और 10 मार्च को चीनी ताइपे से खेलना है। भारतीय टीम को हालांकि इस अहम टूर्नामेंट में अनुभवी मिडफील्डरअंजू तमांग के बिना ही उतरना होग। अंजू चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो गयी है।

ऐसे में उनकी जगह पर करिश्मा शिरवाइकर को शामिल किया गया है। अंजू को अभ्यास सत्र में चोट लगी थी। टीम प्रबंधन के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सा जांच में पाया गया है कि वह टूर्नामेंट से पहले फिट नहीं हो पायेंगी । अंजू ने भारतीय टीम की ओर से अब तक सबसे अधिक मुकाबले खेले हैं और ऐसे में उनका बाहर होना भारतीय टीम के लिए करारा झटका है। पिछले सत्र में अंजू ने ईस्ट बंगाल की टीम की ओर से महिला लीग में भी टीम को खिताबी जीत दिलायी थी। ऐसे में उनकी फॉर्म और अनुभव की कमी टीम को खेलेगी। उनकी जगह पर शामिल करिश्मा किस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं। ये अब देखना होगा।

अभिषेक के फार्म हासिल करने पर युवराज ने खुशी जतायी

बोले- बल्ले से ही आता है असली जवाब

नई दिल्ली। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह टी20 विश्वकप में अपने शिष्य अभिषेक शर्मा की शानदार पारी से बेहद खुश हैं। अभिषेक इस टूर्नामेंट में पहली बार अच्छी पारी खेलने में सफल रहे हैं। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-आठ में 55 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं शुरुआती तीन लीग स्तर के मैचों में वह शून्य पर ही पेवेलियन लौट गये थे जबकि सुपर-8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 रन ही बना पाये थे। ऐसे में वह प्रशंसकों के निशाने पर थे। वहीं अब अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शर्मा ने 30 गेंद में 55 रन बनाकर लय हासिल की है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के भी जड़े। सेमीफाइनल से ठीक पहले अभिषेक के फार्म में आने से उनके गुरु युवराज बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, अच्छी पारी सर अभिषेक, जारी रखो।

अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ संभलकर खेला पर अवसर मिलते हुए बड़े शॉट भी लगा दिये। इस बल्लेबाज ने हर गेंद पर बड़े शॉट लगाने की जगह पर स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया जिससे भी उन्हें लाभ हुआ। इसी को देखते हुए युवराज ने लिखा, असली जवाब तब होता है जब आप अपने बल्ले को ही सारी बात करने देते हैं। अच्छी पारी, सर अभिषेक। ऐसे ही लगे रहिए।

संगकारा ने श्रीलंकाई क्रिकेट में बदलाव की जरुरत बतायी

कोलंबो। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकार ने अपनी मेजबानी में हो रहे आईसीसी टी20 विश्वकप से टीम के बाहर होने पर निराशा जतायी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे क्रिकेट भविष्य को लेकर एक चेतावनी भी है, अगर हम अभी नहीं संभले तो इसी प्रकार पिछड़ते जाएंगे। इसलिए अब हमें बड़े बदलाव की जरुरत है।

संगकारा ने कहा, इस प्रकार बाहर होने सो हर तरफ बहुत दर्द है। प्रशंसक टूट चुके हैं, निराश और गुस्से में हैं। खिलाड़ी भी बेहद आहत हैं। मैं ऐसे ड्रेसिंग रूम में रहा हूं, यह आसान नहीं होता। लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करना एक जिम्मेदारी भी है और सौभाग्य भी। संगकारा ने खिलाड़ियों के जज्बे को समझते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन इससे उबरने के लिए बदलाव जरूरी है। संगकारा ने कहा कि इस हार से हमें सबके लेते हुए खेल ढ़ांच में बदलाव करना होगा। साथ ही कहा, हर स्तर पर हमें काफी कुछ करने की जरुरत है। हम एक जैसी गलतियां दोहराते रहेंगे तो बेहतर परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अधुनिक क्रिकेट तेजी से बदल रहा है और हमें उसके अनुरुप ढ़लना होगा। अगर हमने अपने को नहीं बदला तो हम बाहर हो जाएंगे।

10 साल पहले इसी टीम ने खिताब से किया था दूर; टूट गए थे करोड़ों दिल

विंडीज को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी!

कोलकाता। टी20 विश्व कप 2026 का सुपर-8 चरण रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं जबकि दो स्थानों के लिए लड़ाई जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार यानी 01 मार्च को अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच करो या मरो की स्थिति जैसा है। हालांकि, टीम इंडिया विपक्षी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहेगी।

मौजूदा टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज ग्रुप स्टेज में अजेय रही। सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जबकि अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया था। वहीं, सुपर-8 का अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाने वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच में 72 रन से जीत दर्ज की। रविवार को भारत-वेस्टइंडीज के बीच होने वाला मुकाबला क्वार्टर फाइनल की तरह है। भारतीय टीम अपने घर में खेलने के बावजूद वेस्टइंडीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। इसकी वजह 2016 का टी20 विश्व कप सेमीफाइनल है जिसमें भारतीय टीम को वेस्टइंडीज ने सात विकेट से हराकर खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था।

जब 10 साल पहले टूटे थे करोड़ों प्रशंसकों के दिल- 31 मार्च 2016 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने विराट कोहली के नाबाद 47 गेंद पर बनाए 89 रन की मदद से 2 विकेट पर 192 रन बनाए थे। स्कोर कम नहीं था, लेकिन वेस्टइंडीज की मजबूत बल्लेबाजी ने इस स्कोर को बौना साबित कर दिया। लेंडल सिमंस के 51 गेंदों पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से खेली गई नाबाद 82 और आंद्रे रसेल के 20 गेंदों पर बनाए विस्फोटक 43 रनों की पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने 19.4 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाकर न सिर्फ मैच जीता था बल्कि अपने घर में भारतीय टीम के विश्व कप जीतने का सपना तोड़ा था।

डेरन सैमी की रणनीतियों से रहना होगा सावधान

वेस्टइंडीज इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बनी थी। उस समय टीम के कप्तान रहे डेरन सैमी मौजूदा समय में टीम के मुख्य कोच हैं। कोलकाता में जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डेन्स में उतरेगी, तो निश्चित रूप से 10 साल पहले मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। भारत की 2016 वाली प्लेइंग इलेवन के दो खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, अगले मैच की प्लेइंग इलेवन का भी हिस्सा होंगे। ये दोनों खिलाड़ी वेस्टइंडीज के विश्व कप में चले आ रहे तूफानी और शानदार सफर को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कृषक उन्नति योजनांतर्गत जिले के 40 हजार से ज्यादा किसानों को 205 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि सीधा बैंक खातों में हस्तांतरित

वीर सावरकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक किरण सिंह देव हुए शामिल

जगदलपुर/मूक पत्रिका

राज्य सरकार ने शनिवार को कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जिले के किसानों की झोली खुशियों से भर दी। जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में आयोजित आदान सहायता कार्यक्रम एवं वृहद किसान सम्मेलन में जिले के 40,667 किसानों को 205.95 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लगभग 25 लाख किसानों को 10 हजार 328 करोड़ रुपए से अधिक राशि को किसानों के खातों में हस्तांतरित किया। इस दौरान जगदलपुर में बिलासपुर जिले के कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर देखा गया। जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों से संवाद कर उन्हें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर राशि मिलने सहित होली त्योहार की हार्दिक बधाई दी।जगदलपुर में आयोजित

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतर की राशि को एकमुश्त देकर किसानों की होली त्योहार की खुशी को दुगुनी कर दी है। राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए संवेदनशील होकर पहल कर रही है और वर्तमान बजट में भी उनकी सहायता के लिए अनेक किसान हितैषी प्रावधान किया गया है। जिससे किसानों को उन्नत खेती किसानी के लिए सहूलियत होगी। उन्होंने सहकार से समृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा कि बस्तर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने सहित लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को हरसंभव मदद देने, सिंचाई संसाधनों को बेहतर बनाने प्रयास किया जा रहा है ताकि यहां के निवासियों की आमदनी बढ़े और बस्तर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। उन्होंने बस्तर की बेहतरी और तरक्की में समाज की व्यापक सहभागिता पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी को मिलजुल कर कार्य करने का आव्हान किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक किरण देव ने हल्बी में संबोधित करते हुए किसानों को होली त्योहार की हार्दिक बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार के निर्णय से किसानों के परिवारों में उत्सव का माहौल है उनकी होली की खुशियां बढ़ गई है। यह हमारी सरकार की किसान हितैषी सकारात्मक प्रयास है। इस दौरान अतिथियों द्वारा किसानों को आदान सहायता राशि प्रदाय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वीर सावरकर भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य, जगदलपुर विधायक किरण देव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदलपुर महापौर संजय पांडे, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप, जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष कामदेव बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मोटा धान पर 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ बकावण्ड और बस्तर ब्लॉक के किसानों को मिल रहा है, जहाँ क्रमशः 67.90 करोड़ रुपए और 55.78 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई।

प्रेस क्लब गठन-संजय सिंह अध्यक्ष जगदीश माहेश्वरी उपाध्यक्ष

प्रेस क्लब का सर्वसम्मति से गठन, पत्रकार हितों की मजबूती का संकल्प

सुकमा/मूक पत्रिका

जिले के पत्रकारों की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सुकमा जिला प्रेस क्लब का सर्वसम्मति से गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं, जिससे संगठन को सशक्त और प्रभावी नेतृत्व मिल सके। संघ के अध्यक्ष पद पर संजय (रिंटू) सिंह भदौरिया को मनोनीत किया गया है।

वहीं उपाध्यक्ष के रूप में अमन सिंह भदौरिया एवं जगदीश महेश्वरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव पद की जिम्मेदारी पवन शाहा को, सह सचिव के रूप में रफीक खान को तथा कोषाध्यक्ष के रूप में लीलाधर राठी को नियुक्त किया गया है। संगठन को अनुभवी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु वरिष्ठ पत्रकार पीसा राजेंद्र, जोगराज जैन, आशीष दुबे एवं राजा राठौर को संरक्षक की भूमिका में रखा गया है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संघ को नई दिशा और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अतिरिक्त 13 पत्रकारों को कार्यसमिति सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो संगठन की गतिविधियों, कार्यक्रमों और पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नवगठित संघ ने स्पष्ट किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान,अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष पत्रकारिता के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जिले में पत्रकारों के बीच समन्वय,संवाद और सहयोग की भावना को और मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। जिले के पत्रकारों ने इस गठन को ऐतिहासिक बताते हुए उम्मीद जताई है कि सुकमा जिला पत्रकार संघ आने वाले समय में पत्रकार हितों की आवाज बुलंद करेगा और संगठनात्मक एकता का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। कार्य समिति सदस्य - डमरू राम, जयपाल सिंह,नवीन डांधडे,सुजीत वैदिक,राहुल राजपूत,समीर कीर्तन,ज्ञानेंद्र सिंह,अंकित चौहान,माड़वी पवन,राजकुमार श्रीवाने, गौरव सिंह राठौर,आदर्श शुक्ला,वरुण नायडू,मोहम्मद रफीक

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत गठित दल द्वारा कृषि महाविद्यालय बेमेतरा का मूल्यांकन एवं निरीक्षण

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बेमेतरा में बीते शुक्रवार 27 फरवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत गठित दल द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन की पारगम्यता की जांच के लिए कृषि महाविद्यालय का मूल्यांकन एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। इस तरह के कौशल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं पुरुषों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का ध्यान रखना है जिससे विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्टारों और विभिन्न आयु समूह के वर्गों के बीच रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है जिससे उनमें स्वरोजगार का विकास

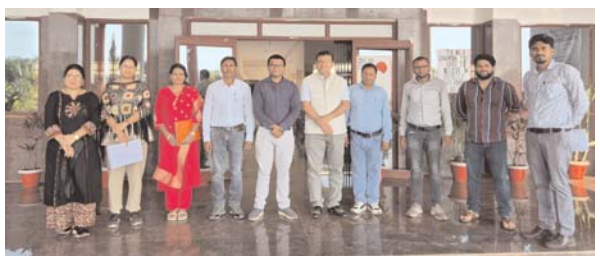

हो। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर संदीप भंडारकर के मार्गदर्शन में कौशल विकास योजना के दल द्वारा कृषि महाविद्यालय का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया उन्होंने कृषि महाविद्यालय में विभिन्न प्रयोगशालाओ , इक्विपमेंट एवं अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जिससे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। शासन द्वारा गठित इस टीम में रोशन वर्मा, सह प्राध्यापक कौशल विभाग, डॉ. श्याम सिंग, सह प्राध्यापक, पौध रोग विज्ञान विभाग, संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कवर्धा, राम कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, धनेश वर्मा, डॉ. जितेंद्र जोशी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, श्रीमति कुंती बंजारे, नोडल अधिकारी, श्रीमति राजेश्वरी कुर्रे सहायक नोडल अधिकारी रेवेंद्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय बेमेतरा उपस्थित रहे।

जिले में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर दी गई भाव पूर्ण विदाई

श्रीफल, शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर किया गया सम्मान

सहायक उप निरीक्षक आनंदी राम सिन्हा ने पुलिस विभाग में लगभग 42 वर्ष 05 माह से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के पुलिस विभाग में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक आनंदी राम सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में उन्हें भाव पूर्ण विदाई दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने सहायक उप निरीक्षक

आनंदीराम सिन्हा के स्वस्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की। वे अब अपने परिवार को भरपूर समय दे पाएंगे। उल्लेखनीय है कि सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा ने पुलिस विभाग में लगभग 42 वर्ष 05 माह से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी। इस दौरान जिला दुर्ग एवं बेमेतरा जिले के विभिन्न थाना/चौकी में अपनी सेवा प्रदान की। पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने श्रीफल, शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया। डीआईजी रामकृष्ण साहू ने कहा कि पुलिस विभाग में सेवा के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने सेवा के दौरान सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई सेवा के दौरान अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए कार्य किये। ज्ञात हो कि सहायक उप निरीक्षक आनंदी राम सिन्हा सन 1983 में आरक्षक के पद पर जिला दुर्ग में भर्ती हुए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा, एसडीओपी बेरला विनय कुमार ने कहा कि सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा ने पुलिस विभाग में शालीन एवं मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई गृह विभाग में संवेदनशील होकर ड्यूटी करनी पड़ती है। इसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। पुलिस परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना करते है। सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा ने अपने सेवाकाल के दौरान अपने खट्टे मीठे अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं स्टाफसे मिले भरपूर सहयोग से अपनी ड्यूटी तत्परतापूर्वक निभाई इसके लिए उन्होंने अपने स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो एवं मुख्यलिपिक उप निरीक्षक (अ) हरिओम विश्वकर्मा, सउनि (अ) अजय कुमार देवांगन, महेन्द्र भुआर्य, एवं सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक आनंदीराम सिन्हा की पत्नी श्रीमती चंद्रिका सिन्हा, पूत्र धीरेन्द्र सिन्हा, रीडर- 1 निरीक्षक कृष्ण कांत सिंह, थाना/चौकी/सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, चंद्रदेव वर्मा, सत्य प्रकाश उपाध्याय, रोशन लाल तोड़े, लेखराम ठाकुर, उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव, राजकुमार साहू, योगेश अग्रवाल, द्वारिका प्रसाद देशलहरे, राकेश साहू, यशवंत जांघेल, सहायक उपनिरीक्षक कवल सिंह नेताम, तुलाराम देशमुख, प्रधान आरक्षक ऐश्वर्य सिंह, सुखेलाल बंजारे, अनिल तिवारी, खोमलाल साहू, एएसपी रीडर महिला प्रधान आरक्षक वर्षा चौबे, आरक्षक मनीष देवांगन, गेल्विन साहू सहित पुलिस कार्यालय के अधि./कर्मचारी उपस्थित रहे।

होली पर 4 मार्च को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ÷होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा)÷ बुधवार 04 मार्च 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश के परिपालन में जिला बेमेतरा में स्थित सभी मदिरा दुकानें उक्त तिथि को पूर्णतः बंद रहेंगी। इसमें निम्नलिखित दुकानें एवं उनसे संलग्न अहाते शामिल हैं समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 (घघ)), समस्त विदेशी / प्रीमियम मदिरा दुकानें (एफएल.-1 (घघ)), समस्त देशी/विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल.-1 (घघ-कम्पोजिट)) 7 समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफएल.-1 (ख-अहाता), एफएल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) 7 आदेशानुसार 04 मार्च 2026 (बुधवार) को उक्त सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे तथा निर्धारित अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।प्रशासन द्वारा नागरिकों से शांति, सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए होली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की गई है।

सीएचसी साजा में 8 हितग्राहियों का हुआ सफल पुरुष नसबंदी आपरेशन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग बेमेतरा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में परिवार नियोजन कार्यक्रम तहत 28 फरवरी 2026 को 8 हितग्राहियों का पुरुष नसबंदी आपरेशन किया गया यह ऑपरेशन कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर मार्गदर्शन में एवं बीएमओ साजा डॉ अश्वनी वर्मा के नेतृत्व पर सर्जन डॉ सतीश चन्द्रवंशी द्वारा किया गया जो कि पूर्णतः सफल रहा ।

÷छोटा परिवार खुशहाल परिवार÷ के संदेश को जिला बेमेतरा के लोग साकार कर रहे है। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि है। जिला बेमेतरा में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश में पुरूष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेमेतरा जिला में पुरूष नसबंदी आपरेशन आयोजित किया गया है। गांव गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ÷मोर मितान मोर संगवारी÷ सम्मेलन के माध्यम से पुरूष नसबंदी आपरेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है।

पुरूष नसबंदी आपरेशन को ÷स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा, जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा÷ की थीम पर चलाया जाता रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के द्वारा बताया गया कि पुरूष नसबंदी में मात्र 10 मिनट का समय लगता है एवं नसबंदी के तुरंत बाद घर जा सकते है। पुरूष नसबंदी के पश्चात् सामान्य कार्य प्रारंभ कर सकते है। जिला बेमेतरा में पुरुष नसबंदी आपरेशन जिला चिकित्सालय बेमेतरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडसरा में पुरूष नसबंदी ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हितग्राही को लेकर आने एवं जागरूकता के उद्देश्य से मोर मितान मोर संगवारी चौपाल के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ द्वारा लक्ष्य दंपत्ति की ग्रामवार सूची तैयार कर आयोजन किया जाता रहा है।

महानदी के तट नंदीगव प्राथमिक शाला में गूंजा योग का संदेशः जुगेन्द्र साहू ने स्वस्थ तन मन का दिया मंत्र

बरमकेला /मूक पत्रिका

विकास खंड बरमकेला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नंदीगाव में आज का दिन बच्चों के लिए खास और प्रेरणादायक रहा। विद्यालय परिसर में योग शिक्षक जुगेन्द्र साहू के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों को योगाभ्यास कराया गया और स्वस्थ जीवनशैली का महत्व समझाया गया। योग शिक्षक जुगेन्द्र साहू ने बच्चों को विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए बताया कि नियमित योग से शरीर स्वस्थ, मन एकाग्र और आत्मविश्वास मजबूत होता है। उन्होंने बच्चों को खान-पान पर विशेष ध्यान देने, जंक फूड से दूर रहने और पौष्टिक आहार अपनाने का संदेश भी दिया।

योग शिक्षक जुगेन्द्र साहू ने कहा–÷बच्चों के जीवन में योग की शुरुआत जितनी जल्दी हो, उतना बेहतर है। योग न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक विकास और अनुशासन भी सिखाता है। यदि बच्चे प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट योग करें और संतुलित आहार लें, तो वे बीमारियों से दूर रहकर पढ़ाई और खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।÷ इस अवसर पर प्रधान पाठक gandaram Ogare शिक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता सरपंच गौरीशंकर जी एवं रिटायर्ड शिक्षिका की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी शिक्षकों ने बच्चों को प्रतिदिन योग करने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। छोटे-छोटे विद्यार्थियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ योगासन किए, जिससे विद्यालय का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। विद्यालय परिवार का मानना है कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर और मजबूत मन की दिशा में यह एक सराहनीय पहल साबित हुई।

भानुप्रतापपुर में शासन का ध्यान खींचने सौंपा ज्ञापन

रसोइयों की जायज मांगों को लेकर शिवसेना का बड़ा कदम

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-कांकेर भानुप्रतापपुर छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले मध्याह्न भोजन रसोइयों की समस्याओं के समाधान हेतु शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने एक सकारात्मक पहल की है। शिवसेना के प्रदेश सचिव महेश वासुदेव दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भानुप्रतापपुर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रसोइयों के मानदेय में वृद्धि और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की है। ज्ञापन सौंपते हुए शिवसेना नेताओं ने विश्वास जताया कि संवेदनशील साय सरकार रसोइयों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। प्रदेश सचिव महेश वासुदेव दुबे ने कहा कि महंगाई के इस दौर में मात्र 2000 रुपये के मानदेय पर कार्य करना रसोइयों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने सरकार को चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए आग्रह किया कि मानदेय में 50त्न वृद्धि के वादे को जल्द अमलीजामा पहनाया जाए ताकि हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ सके।

प्रमुख मांगें जिन पर ध्यानाकर्षण कराया गया

शिवसेना ने रसोइयों के हित में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शासन के समक्ष रखे हैं सम्मानजनक मानदेय रसोइयों के लिए कलेक्टर दर पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की जाए।भविष्य की सुरक्षा रसोइयों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देकर उनके सेवाकाल को सुरक्षित बनाया जाए।आर्थिक सहायता आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। दो महीने की हड़ताल अवधि का रुका हुआ मानदेय तत्काल जारी किया जाए।इन प्रमुख पदाधिकारियों की रही मौजूदगी ज्ञापन सौंपने के दौरान न केवल मांगों पर चर्चा हुई, बल्कि संगठन की मजबूती भी दिखी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनेश नुरूटी, चेतन भुआर्य, भोलाराम नेताम, डिपेंद्र कुंजाम सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित रहे। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर रसोइयों के साथ न्याय करेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।